नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 191
दि. 15.04.2026,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

तमिलनाडु चुनाव में बड़े वादों की बरसात: महिलाओं, किसानों और बुनियादी ढांचे पर भाजपा का फोकस

चेन्नई। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है और इसी बीच Bharatiya Janata Party (भाजपा) ने अपना बहुप्रतीक्षित घोषणापत्र जारी कर चुनावी मुकाबले को नई दिशा दे दी है। इस घोषणापत्र में पार्टी ने महिलाओं, किसानों, युवाओं और बुनियादी ढांचे के विकास को केंद्र में रखते हुए कई बड़े और आकर्षक वादे किए हैं, जो सीधे तौर पर आम जनता के जीवन स्तर को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। खास बात यह है कि घोषणापत्र में आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार सृजन जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भाजपा इस बार राज्य में व्यापक जनाधार बनाने की रणनीति पर काम कर रही है।

सबसे बड़ा और चर्चित वादा महिलाओं को लेकर किया गया है। पार्टी ने घोषणा की है कि राज्य के हर परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह योजना न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक कदम मानी जा रही है, बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिरता को भी मजबूत करने का प्रयास है। इसके अलावा, हर परिवार को एकमुश्त 10,000 रुपये की सहायता देने का वादा भी किया गया है, जो चुनावी माहौल में एक बड़ा आकर्षण बन सकता है। यही नहीं, बढ़ती महंगाई के बीच रसोई गैस के खर्च को कम करने के लिए हर साल तीन एलपीजी सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा भी की गई है, जो सीधे तौर पर मध्यम और निम्न वर्गीय परिवारों को राहत पहुंचाने वाला कदम है।

भाजपा ने अपने घोषणापत्र में सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को भी प्रमुखता दी है। पार्टी ने भगवान मुरुगन के सम्मान में 'थाईपूसम' को राज्य उत्सव घोषित करने का वादा किया है। इसके साथ ही तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर 'कार्तिकई दीपम' की परंपरा को फिर से शुरू करने और उसे संरक्षित रखने की बात कही गई है। यह पहल राज्य की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई मानी जा रही है।

इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी भाजपा ने कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का खाका पेश किया है। पार्टी ने तमिलनाडु के रेल नेटवर्क में व्यापक सुधार का वादा करते हुए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर (चेन्नई-बेंगलुरु और चेन्नई-हैदराबाद), कोयंबटूर-तिरुपुर-सेलम आरआरटीएस, और विलुप्पुरम-चेन्नई सेमी-अर्बन रेल जैसी परियोजनाओं को लागू करने की बात कही है। इसके अलावा चेन्नई को दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों से जोड़ने वाली नई स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों की योजना भी घोषणापत्र का हिस्सा है। इन परियोजनाओं के जरिए न केवल यात्रा को तेज और सुविधाजनक बनाने का लक्ष्य है, बल्कि औद्योगिक और आर्थिक विकास को भी गति देने का प्रयास किया गया है।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर भी पार्टी ने कई ठोस कदमों की घोषणा की है। स्वयं सहायता समूहों (SHG), सहकारी समितियों और एमएसएमई सेक्टर में काम कर रही महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 50 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण देने का वादा किया गया है। साथ ही सरकारी खरीद में 20 प्रतिशत का अनिवार्य कोटा निर्धारित करने की बात कही गई है, जिससे महिला उद्यमियों को बाजार में बेहतर अवसर मिल सकें। इसके अलावा पात्र महिलाओं को ई-स्कूटर खरीदने के लिए 25,000 रुपये की सब्सिडी देने की योजना भी शामिल है, जो उनके दैनिक जीवन को अधिक सुगम बनाने में मदद कर सकती है।

किसानों के लिए भी घोषणापत्र में विशेष प्रावधान किए गए हैं। भाजपा ने केंद्र सरकार की पीएम-किसान योजना में 3,000 रुपये की अतिरिक्त राशि जोड़ने का वादा किया है, जिससे किसानों को सालाना 9,000 रुपये की सहायता मिल सकेगी। 'उझवे थाई' योजना के तहत यह पहल किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। कानून-व्यवस्था और नशा मुक्ति को लेकर भी भाजपा ने सख्त रुख अपनाया है। पार्टी ने राज्य को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लेते हुए विशेष हेल्पलाइन, फास्ट-ट्रैक अदालतों और नारकोटिक्स मामलों के लिए अलग टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की है। इसके अलावा, नशीले पदार्थों की तस्करी और बार-बार अपराध करने वाले गिरोहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, यहां तक कि मृत्युदंड तक का प्रावधान करने की बात कही गई है। समुद्री तस्करी पर नजर रखने के लिए एक विशेष नारकोटिक्स इंटेलिजेंस विंग बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है।

राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भाजपा इस चुनाव में AIADMK और National Democratic Alliance (एनडीए) के साथ मिलकर 27 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में यह घोषणापत्र न केवल पार्टी के विजन को दर्शाता है, बल्कि गठबंधन की चुनावी रणनीति का भी अहम हिस्सा है। भाजपा का प्रयास है कि वह पारंपरिक रूप से द्रविड़ राजनीति के प्रभाव वाले तमिलनाडु में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराए और नए मतदाताओं को अपने पक्ष में आकर्षित करे।

कुल मिलाकर, भाजपा का यह घोषणापत्र 'वेलफेयर प्लस डेवलपमेंट' मॉडल का मिश्रण प्रतीत होता है, जिसमें एक ओर सीधे आर्थिक लाभ देने वाली योजनाएं हैं, तो दूसरी ओर दीर्घकालिक विकास परियोजनाओं का खाका भी शामिल है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता इन वादों को किस नजरिए से देखते हैं और चुनावी मैदान में इसका कितना प्रभाव पड़ता है।

देश की सैन्य कमान में बड़ा बदलाव तय: नए CDS, सेना प्रमुख और उप CDS की दौड़ तेज

नई दिल्ली में इन दिनों देश की सर्वोच्च सैन्य नेतृत्व संरचना को लेकर गहन मंथन जारी है। केंद्र सरकार आने वाले महीनों में भारतीय सशस्त्र बलों के तीन अत्यंत महत्वपूर्ण पदों—चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS), सेना प्रमुख और संभावित उप CDS—पर नियुक्तियों को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। यह केवल नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि भारत की सैन्य रणनीति, समन्वय और भविष्य की रक्षा नीति को दिशा देने वाला निर्णय माना जा रहा है।

वर्तमान सीडीएस General Anil Chauhan का कार्यकाल 30 मई को समाप्त होने जा रहा है। उन्हें पहले आठ महीने का सेवा विस्तार दिया गया था, जिसके दौरान उन्होंने तीनों सेनाओं—थलसेना, वायुसेना और नौसेना—के बीच तालमेल को मजबूत करने के लिए कई अहम पहलें कीं। उनके कार्यकाल में थिएटर कमांड की अवधारणा को आगे बढ़ाने और संयुक्त सैन्य रणनीति को लागू करने पर विशेष ध्यान दिया गया। अब जब उनका कार्यकाल समाप्ति की ओर है, तो सरकार के सामने एक बार फिर यह चुनौती है कि वह इस पद के लिए ऐसा नेतृत्व चुने जो भविष्य की जटिल सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो।

सूत्रों के अनुसार, इस बार सीडीएस पद के लिए एक नया संतुलन स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। अब तक इस पद पर नियुक्त दोनों अधिकारी थलसेना से रहे हैं, ऐसे में इस बार Indian Air Force के किसी वरिष्ठ अधिकारी को यह जिम्मेदारी दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक युद्ध में वायु शक्ति की भूमिका लगातार बढ़ रही है—चाहे वह सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर डिफेंस हो या निगरानी और खुफिया संचालन—ऐसे में वायुसेना के नेतृत्व को शीर्ष स्तर पर प्रतिनिधित्व देना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

इसी के साथ, देश के वर्तमान सेना प्रमुख Upendra Dwivedi भी जुलाई की शुरुआत में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उनके उत्तराधिकारी को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। इस पद के लिए उप सेना प्रमुख सहित लगभग नौ वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल के नाम सामने आ रहे हैं। इनमें वे अधिकारी शामिल हैं जिन्होंने विभिन्न कमानों का नेतृत्व किया है और जिनके पास व्यापक संचालनात्मक अनुभव है। सेना प्रमुख का चयन केवल वरिष्ठता के आधार पर नहीं, बल्कि नेतृत्व क्षमता, रणनीतिक दृष्टि और संकट प्रबंधन कौशल को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में एक और अहम पहलू उभरकर सामने आया है—उप चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (Deputy CDS) का पद। सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस बार पहली बार इस पद पर नियुक्ति करने पर विचार कर रही है। यह पद लेफ्टिनेंट जनरल स्तर का होगा और इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच समन्वय को और अधिक प्रभावी बनाना है। CDS के कार्यभार को बांटने और निर्णय प्रक्रिया को तेज करने में यह पद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विशेषकर ऐसे समय में जब भारत अपनी सैन्य संरचना को अधिक एकीकृत और आधुनिक बनाने की दिशा में काम कर रहा है, उप CDS की नियुक्ति एक बड़ा संस्थागत सुधार साबित हो सकती है।

सरकार की दीर्घकालिक नीति के अनुसार, सीडीएस पद पर तीनों सेनाओं के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बारी-बारी से नियुक्ति की जा सकती है। यदि इस बार वायुसेना के अधिकारी को यह जिम्मेदारी मिलती है, तो भविष्य में Indian Navy के किसी वरिष्ठ अधिकारी को भी यह अवसर दिया जा सकता है। इससे न केवल तीनों सेनाओं के बीच समानता का भाव मजबूत होगा, बल्कि संयुक्त संचालन की अवधारणा को भी बढ़ावा मिलेगा।

इन नियुक्तियों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि वर्तमान वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। चीन के साथ सीमा विवाद, हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, साइबर और स्पेस वॉरफेयर जैसी नई चुनौतियां—इन सभी का सामना करने के लिए भारत को एक मजबूत, समन्वित और दूरदर्शी सैन्य नेतृत्व की आवश्यकता है। CDS और सेना प्रमुख जैसे पद इस दिशा में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।

इसके अलावा, "थिएटर कमांड" जैसे बड़े सैन्य सुधारों को लागू करने के लिए भी एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। यह प्रणाली तीनों सेनाओं को एकीकृत कमांड के तहत लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग और तेज निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो सके।

तनाव के बीच कूटनीति की नई पहल: पाकिस्तान में फिर आमने-सामने आ सकते हैं अमेरिका और ईरान

वेस्ट एशिया में लगातार बढ़ते तनाव और अस्थिरता के बीच वैश्विक कूटनीति एक बार फिर सक्रिय होती नजर आ रही है। इस बार पहल पाकिस्तान की ओर से हुई है, जिसने खुद को एक संभावित मध्यस्थ के रूप में प्रस्तुत करते हुए अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के दूसरे दौर की मेजबानी का प्रस्ताव दिया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहद तनावपूर्ण रहे हैं और कई बार स्थिति टकराव के कगार तक पहुंच चुकी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने भी इस प्रस्ताव पर सकारात्मक संकेत देते हुए स्पष्ट कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ बातचीत के लिए तैयार है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच बयानबाजी तेज है और खाड़ी क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों को लेकर चिंता बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक, यदि सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो अगले दो दिनों में पाकिस्तान की धरती पर दोनों देशों के प्रतिनिधि आमने-सामने बैठ सकते हैं।

पाकिस्तान की यह पहल केवल कूटनीतिक सक्रियता भर नहीं है, बल्कि इसके पीछे उसकी रणनीतिक सोच भी झलकती है। एक ओर वह खुद को अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक जिम्मेदार और प्रभावशाली खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना चाहता है, वहीं दूसरी ओर वह वेस्ट एशिया के तनावपूर्ण माहौल में शांति स्थापित करने की दिशा में योगदान देने का प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान पहले भी विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर मध्यस्थता की भूमिका निभाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन इस बार स्थिति अधिक संवेदनशील और जटिल है।

अमेरिका और ईरान के बीच संबंधों का इतिहास उतार-चढ़ाव से भरा रहा है। परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंध, क्षेत्रीय प्रभाव और सैन्य गतिविधियां ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं, जिनके कारण दोनों देशों के बीच अविश्वास गहराता गया है। हालांकि, समय-समय पर बातचीत के प्रयास भी हुए हैं, लेकिन कोई स्थायी समाधान अब तक सामने नहीं आ सका है। ऐसे में पाकिस्तान द्वारा प्रस्तावित यह वार्ता एक नई उम्मीद के रूप में देखी जा रही है।

इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत भी कूटनीतिक रूप से सक्रिय दिखाई दे रहा है। Narendra Modi और Donald Trump के बीच हाल ही में लगभग 40 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई, जिसमें ईरान से जुड़े हालात पर विस्तार से चर्चा की गई। इस वार्ता में दोनों नेताओं ने खासतौर पर होर्मुज जलडमरूमध्य को खुला रखने की आवश्यकता पर जोर दिया, क्योंकि यह वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। यदि इस मार्ग में किसी प्रकार की बाधा आती है, तो इसका सीधा असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।

भारत के लिए यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसकी ऊर्जा आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से ही पूरा होता है। ऐसे में क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता देने की बात कही है, और इस बार भी उन्होंने उसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पाकिस्तान में प्रस्तावित यह बैठक सफल होती है, तो यह न केवल अमेरिका और ईरान के रिश्तों में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम होगा, बल्कि पूरे वेस्ट एशिया में शांति की संभावनाओं को भी मजबूती मिलेगी। हालांकि, इस प्रक्रिया में कई चुनौतियां भी हैं। दोनों देशों के बीच गहरे अविश्वास को दूर करना आसान नहीं होगा, और किसी भी समझौते तक पहुंचने के लिए कई दौर की बातचीत की आवश्यकता पड़ सकती है।

इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अन्य कारक भी इस प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। रूस, चीन, यूरोपीय संघ जैसे बड़े खिलाड़ी भी इस क्षेत्र में अपनी-अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और उनके हित भी इस वार्ता के परिणामों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तान की यह पहल एक जटिल कूटनीतिक समीकरण का हिस्सा बन सकती है।

कॉर्पोरेट कैंपस में साजिश का साया: नासिक टीसीएस कांड ने खोली संगठित उत्पीड़न की परतें

महाराष्ट्र के नासिक से सामने आया टीसीएस बीपीओ कैंपस कांड केवल एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट ढांचे के भीतर छिपे एक ऐसे खतरनाक तंत्र का संकेत है, जिसने समाज, प्रशासन और उद्योग जगत—तीनों को झकझोर दिया है। देश की प्रतिष्ठित आईटी कंपनी Tata Consultancy Services (टीसीएस) के कैंपस में यौन उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना और जबरन धर्म परिवर्तन जैसे गंभीर आरोपों ने इस घटना को अत्यंत संवेदनशील बना दिया है। जैसे-जैसे विशेष जांच दल (SIT) अपनी जांच को आगे बढ़ा रहा है, इस मामले की परतें खुलती जा रही हैं और हर नई जानकारी पहले से ज्यादा चिंताजनक तस्वीर पेश कर रही है।

अब तक सामने आए तथ्यों के अनुसार, इस पूरे प्रकरण में कम से कम 12 पीड़ितों की पहचान हो चुकी है, जिनमें 11 महिलाएं और 1 पुरुष कर्मचारी शामिल हैं। इन सभी ने अलग-अलग स्तर पर अपने साथ हुए उत्पीड़न की कहानी बताई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन पीड़ितों ने जिन आरोपों का जिक्र किया है, उनमें केवल कार्यस्थल पर शोषण ही नहीं, बल्कि निजी जीवन में हस्तक्षेप, धार्मिक दबाव और मानसिक नियंत्रण जैसे गंभीर पहलू भी शामिल हैं। पुलिस ने अब तक 9 एफआईआर दर्ज की हैं, लेकिन जांच एजेंसियों का मानना है कि यह संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि कई पीड़ित अभी भी सामाजिक दबाव और भय के कारण सामने आने से हिचक रहे हैं।

इस पूरे मामले में जिस नाम ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, वह है एचआर एग्जीक्यूटिव निदा खान। जांच एजेंसियों के अनुसार, निदा खान इस कथित नेटवर्क की मुख्य मास्टरमाइंड के रूप में उभरी हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए टीम लीडर्स के साथ मिलकर कर्मचारियों को निशाना बनाया और उन्हें एक सुनियोजित तरीके से मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के जाल में फंसाया। फिलहाल निदा खान फरार हैं, और पुलिस उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है।

जांच में सामने आए तथ्यों के अनुसार, यह कोई आकस्मिक या व्यक्तिगत घटना नहीं थी, बल्कि एक संगठित सिंडिकेट के तहत संचालित गतिविधि थी। इस नेटवर्क में शामिल लोगों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा था। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कर्मचारियों की प्रोफाइलिंग की जाती थी और फिर उन्हें 'टारगेट' किया जाता था। यह प्रक्रिया बेहद योजनाबद्ध थी, जिसमें पहले दोस्ती, फिर विश्वास और उसके बाद दबाव और शोषण का सिलसिला शुरू होता था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक अनोखी रणनीति अपनाई। चार महिला कांस्टेबल्स को हाउसकीपिंग स्टाफ के रूप में कैंपस में तैनात किया गया, ताकि अंदरूनी गतिविधियों की वास्तविक तस्वीर सामने लाई जा सके। इस अंडरकवर ऑपरेशन से जो जानकारियां मिलीं, उन्होंने जांच को एक नई दिशा दी। यह स्पष्ट हुआ कि एचआर और टीम लीडर्स के बीच गहरा तालमेल था और पूरे ऑपरेशन को बेहद सावधानी से अंजाम दिया जा रहा था।

इस मामले में एक और चौंकाने वाला पहलू तब सामने आया जब जांच एजेंसियों को अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन के संकेत मिले। व्हाट्सएप चैट्स की जांच के दौरान 'इमरान' नाम के एक व्यक्ति का जिक्र सामने आया, जिसके तार मलेशिया से जुड़े बताए जा रहे हैं। SIT अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस नेटवर्क को विदेश से फंडिंग या किसी प्रकार का मार्गदर्शन मिल रहा था। फॉरेंसिक टीम डिलीट की गई चैट्स को रिकवर करने में जुटी है, जिससे और अहम सुराग मिलने की उम्मीद है।

पीड़ितों के बयान इस पूरे मामले को और भी भयावह बनाते हैं। कई कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि उन्हें जबरन धार्मिक प्रथाओं का पालन करने के लिए मजबूर किया गया, उनकी निजी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया और विरोध करने पर उन्हें नौकरी से निकालने या बदनाम करने की धमकी दी गई। कुछ मामलों में शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण के आरोप भी सामने आए हैं। यह सब एक ऐसे वातावरण में हो रहा था, जहां कर्मचारियों को सुरक्षित और पेशेवर माहौल मिलना चाहिए था। इस घटना ने कॉर्पोरेट सेक्टर में कार्यस्थल की सुरक्षा और निगरानी प्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक प्रतिष्ठित कंपनी के भीतर इस तरह की गतिविधियों का लंबे समय तक जारी रहना यह दर्शाता है कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कहीं न कहीं बड़ी चूक हुई है। पुलिस ने इस संबंध में टीसीएस प्रबंधन से भी जवाब मांगा है और यह जानने की कोशिश की जा रही है कि भर्ती प्रक्रिया, निगरानी तंत्र और शिकायत निवारण प्रणाली में क्या कमियां थीं।

सामाजिक दृष्टिकोण से भी यह मामला बेहद महत्वपूर्ण है। यह केवल कानून और व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि समाज में व्याप्त भय, दबाव और चुप्पी की संस्कृति को भी उजागर करता है। यदि पीड़ित समय रहते सामने नहीं आते, तो ऐसे नेटवर्क और मजबूत होते जाते हैं। इसलिए इस मामले में पीड़ितों का आगे आना एक साहसिक कदम माना जा रहा है, जो अन्य लोगों को भी अपनी आवाज उठाने के लिए प्रेरित कर सकता है। फिलहाल पुलिस और जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की हर कड़ी को जोड़ने में जुटी हैं। आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं और कई नए खुलासे भी सामने आ सकते हैं। यह मामला केवल नासिक या एक कंपनी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे देश के लिए एक चेतावनी है कि कार्यस्थलों पर सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही को और मजबूत करना समय की मांग है। अंततः, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस मामले में न्याय किस गति से और किस दिशा में आगे बढ़ता है। यदि दोषियों को सख्त सजा मिलती है, तो यह न केवल पीड़ितों के लिए न्याय होगा, बल्कि पूरे समाज के लिए एक मजबूत संदेश भी होगा कि किसी भी प्रकार का शोषण और उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

संपादकीय

महंगाई और स्थिर वेतन के बीच बढ़ी खाई

कोरोना संकट के बाद पटरी पर लौटती वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को दुनिया के कई भागों में जारी युद्ध व संघर्ष ने फिर पटरी से उतार दिया है। महाशक्तियों की महत्वाकांक्षा मानवता और आम आदमी के जीवन पर भारी पड़ी है। यूक्रेन युद्ध ने दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं और यूरोप की ऊर्जा आपूर्ति को बाधित जरूर किया, लेकिन उसका असर उतना व्यापक नहीं था, जितना खाड़ी युद्ध का रहा है। जाहिरा तौर पर वैश्विक आपूर्ति शृंखला बाधित होने से आम आदमी के जीवन पर बहुत नकारात्मक असर पड़ा है। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की जीवन शैली व थाली पर गहरा प्रभाव डाला है। अमेरिका के साम्राज्यवादी मंसूबों और इस्राइल की आक्रामकता से उपजे खाड़ी संकट ने एशिया ही नहीं, बल्कि यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका की ऊर्जा आपूर्ति शृंखला को संकट में डाल दिया है। संयुक्त राष्ट्र की विफलता के चलते आज दुनिया में 'जिसकी लाठी, उसकी भैंस' वाली कहावत चरितार्थ हुई है। जिसका सीधा असर महंगाई वृद्धि के रूप में सामने आया है। एक ओर ईंधन संकट और उससे बुरी तरह प्रभावित जनजीवन आक्रोश का कारक बना है। विडंबना यह है कि इस महंगाई के बीच कामगारों के वेतन सिकुड़ने लगे हैं। जीवनयापन कठिन होते और कोई समाधान न निकलते देख श्रमिकों का आक्रोश सड़क तक पहुंचने लगा है। सोमवार को उत्तर प्रदेश के नोएडा में फैक्ट्रियों के श्रमिकों द्वारा किया गया हिंसक प्रदर्शन इस संकट की परिणति ही है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा की औद्योगिक नगरी मानेसर में भी पुलिस व श्रमिकों के बीच हिंसक झड़पों की खबरें आई हैं। ये टकराव भारतीय औद्योगिक तंत्र की विसंगतियों की ही याद दिलाते हैं। इस तरह के हिंसक संघर्ष हमारी कानून-व्यवस्था की विफलता को भी उजागर करते हैं। वहीं बताते हैं कि श्रमिक वर्ग, उद्योग और राज्य सरकार के बीच कहीं न कहीं संवाद की कमी है। यही वजह है कि वेतन बढ़ाने की मांग के समर्थन में शुरू हुआ मार्च कालांतर आगजनी, तोड़फोड़ व यातायात बाधित करने में तब्दील हो गया। निश्चित तौर पर समय रहते इस श्रमिक असंतोष को भांपते हुए बेहतर ढंग से संवाद किया जाता तो शायद टकराव की स्थिति पैदा न होती। दरअसल, सरकारों की तरफ से तो कहा जा रहा है कि देश में ईंधन व गैस आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं है, लेकिन जमाखोरी व प्रशासन की उदासीनता से इसकी कालाबाजारी जारी है। श्रमिक वर्ग जो छोटे गैस सिलेंडरों से जीवन-यापन करता था, उसमें व्यवधान पैदा हो गया। नियंत्रित गैस आपूर्ति से छोटे गैस सिलेंडर भरने का धंधा ठप हो गया। शायद सरकारों को भी इस बात का अहसास नहीं था कि कितना बड़ा श्रमिक वर्ग छोटे गैस सिलेंडरों को भरने के काले धंधे पर निर्भर है। यही वजह है कि हिमाचल समेत कई राज्यों में खाना पकाने के संकट के चलते श्रमिकों के घर लौटने के मामले प्रकाश में आए हैं। लेकिन इस संकट को शासन-प्रशासन के स्तर पर गंभीरता से नहीं लिया गया। निर्विवाद रूप से बढ़ती महंगाई और स्थिर वेतन के बीच बढ़ती खाई से अशांति की जड़ें गहरी होती जा रही हैं। औद्योगिक केंद्रों में कामगार पश्चिम एशिया युद्ध के चलते बढ़ी महंगाई के कारण दबाव में अपना गुजारा करने के लिये संघर्ष कर रहे हैं। निस्संदेह, हरियाणा द्वारा न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का निर्णय इस गंभीर वास्तविकता की स्वीकृति को ही दर्शाता है। लेकिन यह भी हकीकत है कि तात्कालिक उपाय के रूप में बातचीत और शिकायतों का फौरी निवारण कारगर विकल्प नहीं हो सकते। हालांकि, अधिकारी अशांति फैलाने में निहित स्वार्थी तत्वों की भूमिका की जांच कर रहे हैं, लेकिन ये घटनाएं व्यवस्थागत अविश्वास को भी दर्शाती हैं। दरअसल, श्रमिकों का उपेक्षित महसूस करना वातावरण को अस्थिर बनाता है। लेकिन यह एक हकीकत है कि दीर्घकालिक आर्थिक परिवर्तन के लिये विनिर्माण की महत्वाकांक्षाएं स्थिर-प्रेरित कार्यबल के बिना संभव नहीं हैं। औद्योगिक अशांति केवल उत्पादन-निवेश तक ही सीमित नहीं रहती। इससे आपूर्ति शृंखला बाधित होने और निवेशकों का भरोसा कम होने की आशंका भी पैदा होती है। निस्संदेह, आर्थिक प्रगति समावेशी हो। शासन को श्रमिक हितैषी होना चाहिए। विश्वास निर्माण से ही हमारे कारखाने विकास का इंजन बन सकते हैं।

जंगलों की कम होती ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने की क्षमता

> जंगल कार्बन सिंक का काम करते हैं, वे जितना कार्बन छोड़ते हैं उससे कहीं ज्यादा मात्रा में उसे हटाते हैं। धीरे-धीरे बढ़ने वाले घने पेड़ों ने दशकों तक तनों में कार्बन को बंद रखा, क्योंकि ठोस लकड़ी के हर इंच में ज्यादा पदार्थ समा सकता है। तेजी से बढ़ने वाले पेड़ अक्सर कम उम्र में मर जाते हैं। उनके तने हल्के होते हैं, इसलिए उनमें जमा कार्बन तूफान और क्षय से जल्दी हवा में वापस चला जाता है।

दुनिया के जंगल हमारे पारिस्थितिक तंत्र का आधार हैं और ग्लोबल वार्मिंग से लड़कर पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन अब उनकी विशिष्ट भूमिका कमजोर हो रही है क्योंकि जंगलों में तेजी से बढ़ने वाले पेड़ों की भरमार हो रही है और लंबे समय तक जीने वाली प्रजातियां तेजी से गायब हो रही हैं। स्थिर और लंबे जीवनकाल वाले पेड़ों की जगह तेजी से बढ़ने वाले पेड़ों को रखना टिम्बर इंडस्ट्री और जंगल की आग के बाद जल्दी संभलने के लिए फायदेमंद है लेकिन बदलते मौसम का सामना करते समय यह जंगलों को बहुत ज्यादा खतरे में डालता है।

डेनमार्क की ओरहुस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने 31,001 पेड़ों की प्रजातियों का वैश्विक विश्लेषण करके बताया है कि तेजी से बढ़ने वाले पेड़ किन जंगलों में हावी हो रहे हैं। डेनिश वैज्ञानिक जेन्स-क्रिश्चियन स्वेनिंग ने नक्शों का इस्तेमाल करके दिखाया कि धीरे-धीरे बढ़ने वाले, खास किस्म के पेड़ तेजी से बढ़ने वाली प्रजातियों के आगे हार रहे हैं। स्वेनिंग ने उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय इलाकों में ऐसे कई छोटे पेड़ों का उल्लेख किया है जिनके गायब होने की संभावना सबसे ज्यादा है। एक बार जब तेजी से बढ़ने वाले पेड़ किसी जगह पर हावी हो जाते हैं, तो तूफान, सूखा और कीड़े उस जंगल के बड़े हिस्से को एक साथ गिरा सकते हैं।

दरअसल, लकड़ी काटने, सड़क बनाने और आग लगने से खुली धूप वाली जगहें बन जाती हैं, जहां तेजी से बढ़ने वाले पेड़ बहुत जल्दी फैल जाते हैं। हल्की पत्तियों और मुलायम लकड़ी की वजह से ये पेड़ तेजी से बढ़ते हैं। सूखे या गर्मी की वजह से पानी की कमी होने पर भी ऐसे पेड़ों का बढ़ना जारी रहता है। इन पेड़ों में लकड़ी का घनत्व कम होता है, जिसकी वजह से इनके तने आसानी से टूट जाते हैं और जल्दी सूख जाते हैं। विषम परिस्थितियों में हल्की लकड़ी वाले पेड़ों के मरने की संभावना अधिक होती है। लंबे समय तक चलने वाले पेड़ धीरे-धीरे बढ़ते थे। मौसम खराब होने पर उनकी गहरी जड़ें और मजबूत तने जंगल को एक साथ बनाए रखते थे। घनी लकड़ी और मजबूत पत्तियों ने उन्हें सूखे और कीड़ों से बचने में मदद की।

हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने ऐसे पेड़ों के टिकाऊपन को जलवायु सुरक्षा से जोड़ा है। इस तरह के पेड़ जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र की रीढ़ हैं और स्थिरता और कार्बन भंडारण में योगदान देते हैं। जैसे-जैसे तूफान, कटाई और गर्मी से जंगलों पर दबाव बढ़ता है, पेड़ों की बाहरी प्रजातियां रोशनी, पानी और पोषक तत्वों के लिए मूल पौधों को घेर लेती हैं। यह दबाव दुर्लभ स्थानीय पेड़ों को खत्म होने के करीब ला सकता है। उष्णकटिबंधीय जंगलों में कई पेड़ों की प्रजातियां छोटे-छोटे इलाकों में मिलती हैं, इसलिए कुछ पेड़ों के खत्म होने से पूरा खाद्य चक्र तेजी से कम हो सकता है।

जंगल कार्बन सिंक का काम करते हैं, वे जितना कार्बन छोड़ते हैं उससे कहीं ज्यादा मात्रा में उसे हटाते हैं। धीरे-धीरे बढ़ने वाले घने पेड़ों ने दशकों तक तनों में कार्बन को बंद रखा, क्योंकि ठोस लकड़ी के हर इंच में ज्यादा पदार्थ समा सकता है। तेजी से बढ़ने वाले पेड़ अक्सर कम उम्र में मर जाते हैं। उनके तने हल्के होते हैं, इसलिए उनमें जमा कार्बन तूफान और क्षय से जल्दी हवा में वापस चला जाता है। इससे जंगल लंबे समय तक कार्बन जमा करने में कम असरदार हो जाते हैं। सही पेड़ों के बिना जंगल उन पक्षियों और स्तनपायी जीवों को खो सकते हैं जो बीज फैलाते हैं, जिससे तूफान या आग के बाद जंगल में रिकवरी धीमी हो जाती है। जंगल के प्रबंधक अक्सर जल्दी फसल के लिए तेजी से बढ़ने वाले पेड़ों को पसंद करते हैं, लेकिन जब पौधों में धीमी गति से बढ़ने वाली प्रजातियां भी शामिल होती हैं, तो जंगल लंबे समय तक अपनी मजबूती बनाए रख सकते हैं। ज्यादा पेड़ चुनने से दुर्लभ आनुवांशिकी सुरक्षित रहती है और जब मौसम का तनाव बढ़ता है, यह जंगल में पुराने विकास वाले गुणों को बनाए रखती है।

एक अन्य अध्ययन में वैज्ञानिकों ने जंगलों की एक और भूमिका को उजागर किया है। अध्ययन में पाया गया कि वन की मिट्टी जलवायु परिवर्तन में जितना योगदान दे रही है, उसका हमें अंदाजा नहीं है। यह साल दर साल चुपचाप हवा से मीथेन को अवशोषित करती रहती है। दक्षिण-पश्चिम जर्मनी में लिए गए नए दीर्घकालिक मापों से पता चलता है कि कुछ वनों में यह भूमिगत मीथेन अवशोषण क्षमता कम होने के बजाय लगातार मजबूत होती जा रही है।

जर्मनी के गोटिंगेन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने लगभग 25 वर्षों तक 13 वन भूखंडों में मीथेन के मूवमेंट का अध्ययन किया और पाया कि मिट्टी की मीथेन अवशोषण क्षमता में प्रति वर्ष लगभग 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह निरंतर वृद्धि नम और शुष्क दोनों मौसमों और धीरे-धीरे बढ़ते तापमान के दौरान देखी गई। यह वृद्धि इस धारणा को चुनौती देती है कि जलवायु परिवर्तन से मिट्टी की मीथेन अवशोषण क्षमता में एक समान कमी आएगी।

नया अध्ययन इस बारे में भी नए सवाल खड़े करता है कि कुछ वन दूसरों की तुलना में तेजी से क्यों बेहतर हो रहे हैं। वनों के सूक्ष्मजीव मीथेन को अवशोषित करते हैं। कम वर्षा के कारण मिट्टी में वायु के लिए अधिक स्थान बचता है, जिससे मीथेन सतह के पास रहने के बजाय तेजी से नीचे की ओर जा सकती है। शुष्क मिट्टी में हवा से भरे छिद्र अधिक होते हैं जिससे मीथेन और ऑक्सीजन दोनों मिट्टी में आसानी से प्रवाहित हो जाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि मीथेन का उपभोग करने वाले सूक्ष्मजीवों को कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है।

जांचे गए भूखंडों में शोधकर्ताओं ने मीथेन के अधिक अवशोषण को मिट्टी की कम नमी और धीरे-धीरे बढ़ने वाले मिट्टी के तापमान से जोड़ा। मीथेनोट्रोफ्स नामक सूक्ष्मजीव मीथेन का ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। एक बार जब मीथेन ऊपरी मिट्टी तक पहुंच जाती है तो ये जीव विभिन्न प्रतिक्रियाओं के जरिए उसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में विखंडित कर देते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि अत्यधिक शुष्क परिस्थितियां सूक्ष्मजीवों की गतिविधि को दबा सकती हैं, जबकि लंबे समय तक गीली मिट्टी ऑक्सीजन के स्तर को कम कर देती है और मीथेन उत्पादक सूक्ष्मजीवों को हावी होने का अवसर देती है।

नासा के अनुसार मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक ऊष्मा अवशोषित करती है, लेकिन यह केवल 7 से 12 वर्षों तक ही बनी रहती है। जब मिट्टी मीथेन को अवशोषित करती है, तो यह वायुमंडल में पहुंचने वाली मीथेन की मात्रा को कम कर देती है, जिससे आने वाले वर्षों में ग्लोबल वार्मिंग का दबाव कम हो जाता है। वन की मिट्टी को इस सेवा के लिए अक्सर श्रेय नहीं दिया जाता। अधिक मीथेन अवशोषण से समस्या का समाधान अपने आप नहीं हो जाएगा, लेकिन इससे उत्सर्जन में कटौती होने तक कुछ समय मिल सकता है।

प्रेरणा

शब्दों का बिखराव और लौटती हुई चोट

प्राचीन भारत के महान आचार्य Chanakya केवल राजनीति और कूटनीति के ही ज्ञाता नहीं थे, बल्कि मानव स्वभाव की गहराइयों को समझने वाले एक अद्भुत मनोवैज्ञानिक भी थे। उनके आश्रम में शिक्षा केवल शास्त्रों तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन के हर छोटे-बड़े व्यवहार में छिपे सत्य को समझाने का प्रयास किया जाता था। उसी आश्रम में एक शिष्य था, जिसकी आदत धीरे-धीरे पूरे वातावरण को विषाक्त बना रही थी। उसे दूसरों की बातें सुनना और फिर उन्हें तोड़-मरोड़ कर इधर-उधर पहुंचाना अच्छा लगता था। उसे लगता था कि यह एक प्रकार का मनोरंजन है, एक खेल है, जिसमें वह बिना किसी दंड के शामिल हो सकता है। लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उसके शब्द केवल हवा में उड़ने वाली ध्वनियां नहीं हैं, बल्कि वे लोगों के मन में गहरे उतरकर संबंधों को तोड़ने की क्षमता रखते हैं।

धीरे-धीरे आश्रम का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले शांति और सौहार्द था, वहां अब संदेह और अविश्वास पनपने लगा। छोटी-छोटी बातों पर विवाद होने लगे, मित्रता में दरार आने लगी और लोग एक-दूसरे से दूरी बनाने लगे। यह सब उस एक शिष्य की आदत का परिणाम था, लेकिन कोई सीधे तौर पर उसे दोषी नहीं ठहरा पा रहा था। वह चुपचाप अपनी भूमिका निभा रहा था और दूसरों के बीच पैदा हो रहे तनाव को देखकर भीतर ही भीतर आनंदित होता था।

एक दिन आचार्य ने उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने उसे डांटा नहीं, न ही कोई लंबा उपदेश दिया। उन्होंने बस एक तकिया उसके हाथ में थमा दिया और कहा कि वह पूरे गांव में घूमकर उसकी रूई को हवा में उड़ाता जाए। शिष्य को यह कार्य अजीब लगा, लेकिन उसने बिना सवाल किए वैसा ही किया। वह गांव की गलियों में घूमता रहा और तकिए की रूई को हवा में बिखेरता रहा। उसे यह एक निरर्थक काम लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद गुरुजी इसके पीछे कोई गहरा अर्थ छिपाए हुए हैं।

जब वह वापस लौटा, तो आचार्य ने उससे कहा कि अब वह उन सभी रूई के टुकड़ों को वापस इकट्ठा करके ले आए। यह सुनकर शिष्य हंस पड़ा। उसे लगा कि यह तो असंभव है। हवा में उड़ चुके उन छोटे-छोटे टुकड़ों को कैसे वापस लाया जा सकता है? उसने विनम्रता से कहा कि यह कार्य संभव नहीं है, क्योंकि वे टुकड़े अब हर दिशा में बिखर चुके होंगे।

तब आचार्य ने उसे शांत स्वर में समझाया कि जैसे वह रूई के टुकड़े वापस नहीं ला सकता, वैसे ही उसके द्वारा फैलाए गए शब्द भी कभी वापस नहीं आ सकते। एक बार जब कोई बात किसी के मन में पहुंच जाती है, तो वह वहां अपनी छाप छोड़ जाती है। चाहे बाद में सच सामने आ जाए या व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर ले, लेकिन जो प्रभाव पहले ही पड़ चुका होता है, उसे पूरी तरह मिटाना लगभग असंभव होता है।

यह सुनते ही शिष्य के भीतर एक गहरी समझ जागी। उसे अहसास हुआ कि वह जो अब तक एक खेल समझ रहा था, वह वास्तव में दूसरों के जीवन में अशांति और पीड़ा का कारण बन रहा था। उसका 'आनंद' दूसरों के दर्द पर आधारित था, और यह आनंद क्षणिक था, लेकिन उसका प्रभाव दीर्घकालिक और गहरा था। उसने पहली बार अपने व्यवहार के परिणामों को इतने स्पष्ट रूप में देखा।

यह कथा केवल उस शिष्य की नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की है, जो बिना सोचे-समझे शब्दों का प्रयोग करता है। चुगली, निंदा और अफवाहें समाज में एक ऐसी आग की तरह फैलती हैं, जो धीरे-धीरे संबंधों को जला देती हैं। अक्सर लोग यह सोचकर ऐसी बातें करते हैं कि इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि हर शब्द एक ऊर्जा है, जो किसी न किसी रूप में वापस लौटती है।

जब हम किसी के बारे में गलत या अधूरी जानकारी फैलाते हैं, तो हम केवल उस व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि पूरे वातावरण को प्रभावित करते हैं। विश्वास, जो किसी भी संबंध की नींव होता है, धीरे-धीरे कमजोर होने लगता है। और जब विश्वास टूटता है, तो उसे फिर से जोड़ना अत्यंत कठिन हो जाता है।

आज के समय में, जब संचार के साधन इतने तेज और व्यापक हो गए हैं, तब इस कहानी का महत्व और भी बढ़ जाता है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एक छोटी सी बात पल भर में हजारों लोगों तक पहुंच सकती है। ऐसे में यदि हम बिना सत्यापन के किसी बात को आगे बढ़ाते हैं, तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यह आधुनिक युग का वही 'रूई का तकिया' है, जिसकी उड़ाई गई बातों को वापस लाना असंभव हो जाता है।

इसलिए आवश्यक है कि हम अपने शब्दों के प्रति सजग रहें। बोलने से पहले यह सोचें कि क्या हमारी बात किसी को आहत कर सकती है, क्या यह पूरी तरह सत्य है, और क्या इसे कहना वास्तव में आवश्यक है। यदि इन तीनों प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक नहीं है, तो बेहतर है कि हम मौन को चुनें।

चाणक्य की यह शिक्षा हमें यह भी बताती है कि सुधार हमेशा संभव है, लेकिन उसके लिए पहले अपनी गलती को स्वीकार करना जरूरी है। जब वह शिष्य अपनी भूल को समझ गया, तभी उसके भीतर परिवर्तन की शुरुआत हुई। यही जीवन का सत्य है—ज्ञान तब तक अधूरा है, जब तक वह हमारे व्यवहार में नहीं उतरता।

अंततः, शब्द हमारे सबसे शक्तिशाली साधनों में से एक हैं। वे निर्माण भी कर सकते हैं और विनाश भी। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उनका उपयोग किस प्रकार करते हैं। यदि हम उन्हें समझदारी और संवेदनशीलता के साथ प्रयोग करें, तो वे संबंधों को मजबूत बना सकते हैं। लेकिन यदि हम उन्हें लापरवाही से इस्तेमाल करें, तो वे वही बन जाते हैं जो उस तकिए की रूई थी—बिखरे हुए, अनियंत्रित और कभी वापस न आने वाले।

आंबेडकर का जीवन ही उनका संदेश

महापुरुषों के क्रियाकलाप ही उनका संदेश होते हैं। यही कारण है कि लोग दुनिया के सभी शीर्ष नायकों के जीवन-वृत्तों में गहरी दिलचस्पी दर्शाते हैं। डॉ. भीमराव आंबेडकर के जीवन संघर्ष के प्रति भी दुनिया में जिज्ञासुओं की संख्या बढ़ रही है। आज उनकी प्रासंगिकता पर विचार करें तो एक प्रचलित लोक कहावत याद आती है, 'काम सबको प्यारा होता है, चाम किसी को नहीं।' इसमें दो मत नहीं कि आंबेडकर भारत भूमि के महा कमेरे सपूत थे। उन्होंने जबसे होश संभाला, उत्तरोत्तर स्वयं को बौद्धिक श्रम की साधना में झोंकते चले गए। बड़ा विजन, बड़े सपने और फिर उनको हासिल करने के लिए सामर्थ्यवान बनने की निरंतर तत्परता की उनकी जैसी दूसरी मिसाल नहीं है। कबीरपंथी पिता सूबेदार रामजी ने उन्हें पहला पाठ पढ़ाया कि यदि तुम्हें अस्पृश्य-जातियों को सामाजिक गुलामी से मुक्ति दिलानी है तो ज्ञान की सत्ता से स्वयं को समर्थ बनाना होगा। ज्ञान से ही ज्ञान का जवाब दिया जा सकता है। सो पिता की मंशा समझ आई और पढ़ाई को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया, पर पढ़ाई के मार्ग में अस्पृश्यता और जाति-हिकारत कदम-कदम पर अवरोध खड़े कर रही थीं। ऐसे परिवेश में दसवीं पास कर लेने पर उनका सम्मान किया गया। वे अस्पृश्य समुदाय के दसवीं पास पहले विद्यार्थी थे। शिक्षा-उपाधियों के उनके कीर्तिमान अध्ययन की निरंतरता के ही परिणाम हैं। अन्यथा स्नातक का उनका परीक्षाफल एक औसत छात्र की छवि ही सामने लाता है। अपनी पैदायशी सुपरमैन वाली धारणा को उन्होंने अपने साक्षात्कारों में स्वयं ही तोड़ा। 13 अप्रैल, 1947 को 'साप्ताहिक नवयुग' में अपने साक्षात्कार में उन्होंने बताया था कि मेरी बीए में थोड़े ही अंकों से सेकेंड डिवीजन रह गई। इंटरमीडिएट में कुल 600 में 223 अंक ही आए थे। इस बाबत उन्होंने कहा था कि अगर कोई मेरे बीए तक के परीक्षा परिणाम देख कर भविष्यवाणी करता कि यह लड़का आगे चल कर इतनी उपलब्धियां प्राप्त करेगा तो उसे पागल करार दिया जाता। फिर भी उनके अध्ययन और लेखन का चुनाव, रिसर्च की गुणवत्ता और देश समाज के संदर्भ में उसकी उपयोगिता महत्वपूर्ण है। उनके शोध के निष्कर्षों की रोशनी में ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले अमर्त्य सेन ने भी गरीबी को समझने के लिए डा. आंबेडकर के रिसर्च को श्रेय दिया था। राष्ट्रीय एकता को लेकर डॉ. आंबेडकर न केवल चिंतित रहते थे, बल्कि उन्होंने पंथ के आधार पर भारत विभाजन रोकने की सलाह भी दी थी। 'थॉट्स ऑन पाकिस्तान' पुस्तक लिखकर उन्होंने दोनों पक्षों को समझाया भी था। जिन्ना को समझाया था कि एकता से हल निकालें, बंटवारा करा कर पछताएंगे। जिन्ना ने उन्हें अनसुना करते हुए कहा, 'मैं आपकी किताब पढ़ चुका हूं, डॉ. आंबेडकर यह आपकी राय है, हमारा फैसला नहीं है।' बाबा साहब दूरद्रष्टा थे। उन्होंने तभी बता दिया था कि विभाजन से स्थायी शांति और प्रगति स्थापित नहीं होगी। आधे मुसलमान भारत और आधे पाकिस्तान में, इससे समाधान नहीं होगा, परंतु उनकी किसी ने नहीं सुनी।

भारत-पाकिस्तान संबंधों को लेकर डॉ. आंबेडकर की शंकाएं सही साबित हुईं। आज भी दोनों में प्रेम, सहयोग, शांति और सद्भाव नहीं है। पाकिस्तान पोषित आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को भारी धन-बल खर्च करने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान भी जब तब हथियार भांजता रहता है। यदि दोनों देश अविभाजित होते तो युद्ध सामग्री पर खर्च होने वाली मोटी धनराशि देश के आर्थिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास पर खर्च होती है।

अछूतों को आत्मनिर्भर और सामाजिक रूप से समर्थ बनाने के उद्देश्य से डॉ. आंबेडकर गोलमेज सम्मेलन से पृथक निर्वाचन का अधिकार लेकर आए। इस पर गांधी जी ने कहा, 'अस्पृश्य मेरे दिल के टुकड़े हैं। मैं उन्हें अलग नहीं होने दूंगा।' तत्कालीन मीडिया ने भी पृथक निर्वाचन को ऐसे पेश किया जैसे पाकिस्तान की तरह डॉ. आंबेडकर कोई अलग दलितस्थान बनाने जा रहे हों। गांधी जी ने पूना की यरवदा जेल में आमरण अनशन कर दिया। डॉ. आंबेडकर पर चारों ओर से दबाव डाला गया कि बापू के प्राण बचाओ। वे धर्म संकट में थे। गांधीजी के प्राणों की रक्षा करें या अस्पृश्यों के हितों-अधिकारों की रक्षा? आखिर राजनीतिक सत्ता, प्रशासनिक एवं राजकीय सेवाओं में निर्धारित प्रतिनिधित्व के आधार पर पूना पैक्ट हो गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि समझौते पर नेक नीयत से अमल नहीं हुआ। दस वर्ष के भीतर प्रतिनिधित्व पूरा होने का आश्वासन आज तक पूरा नहीं हुआ। उच्च शिक्षा, न्यायपालिका, मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं प्रशासनिक उच्च स्तर पर प्रतिनिधित्व पूरा होना तो दूर, उपस्थिति तक नगण्य बनी हुई है। भारत में जातिभेद की तरह अमेरिका में नस्लभेद की समस्या थी। उसमें समावेशी नीतियों को लागू करके अश्वेतों को उद्योग, मीडिया, कला, सिनेमा, राजनीति, खेल, संगीत सब क्षेत्रों में समावेश कर लिया। भारत के आधुनिक सेवा क्षेत्र में दलितों का उचित समावेश नहीं है। नतीजा उन्हें देश को अमेरिका बनाने का अवसर नहीं मिल रहा है। बेशक हम विकासशील हैं, परंतु संतुलन और समग्रता में उसे विकसित बनाने वाले नागरिकों को मौके देने से राष्ट्रीय निर्माण में तेजी आएगी।

अभियान

केदारनाथ: जहां हिमालय की नीरवता में शिव का अनंत प्रकाश साक्षात होता है

भारत की आध्यात्मिक चेतना में कुछ स्थल ऐसे हैं, जो केवल आस्था के केंद्र नहीं बल्कि स्वयं में एक जीवंत अनुभव होते हैं। Kedarnath Temple ऐसा ही एक पवित्र धाम है, जहां पहुंचकर मनुष्य अपने भीतर के मौन से संवाद करना सीखता है। समुद्र तल से लगभग 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर हिमालय की विराट गोद में एक ऐसे स्थान पर विराजमान है, जहां प्रकृति और परमात्मा का मिलन सहज रूप से महसूस किया जा सकता है। चार धाम यात्रा का तीसरा पड़ाव होने के कारण इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, लेकिन इसकी वास्तविक महत्ता उस आध्यात्मिक ऊर्जा में है, जो यहां हर क्षण स्पंदित होती रहती है।

ज्योतिर्लिंगों की परंपरा में केदारनाथ का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। 'ज्योतिर्लिंग' का अर्थ है वह दिव्य प्रकाश स्तंभ, जो शिव के अनंत और निराकार स्वरूप का प्रतीक है। केदारनाथ को 'केदारम' के नाम से भी जाना जाता है और इसे अन्य सभी शिव धामों से श्रेष्ठ माना गया है। 'केदार' का अर्थ है भूमि या क्षेत्र और 'नाथ' का अर्थ है स्वामी, अर्थात यह वह स्थान है जहां शिव स्वयं इस क्षेत्र के अधिपति के रूप में निवास करते हैं। प्राचीन ग्रंथों में इस पूरे क्षेत्र को 'केदारखंड' कहा गया है, जो इसकी पौराणिकता और आध्यात्मिक गहराई को दर्शाता है।

मान्यता है कि यह स्थान उतना ही प्राचीन है जितनी स्वयं सृष्टि। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा का रूप धारण किया, तब उन्होंने इसी स्थान को अपना निवास बनाया। यह स्थल देवताओं के लिए भी दुर्लभ माना गया है, क्योंकि यहां शिव की उपस्थिति अत्यंत सघन रूप में अनुभव होती है। सतयुग में महात्मा उपमन्यु ने यहां कठोर तपस्या की और शिव को प्रसन्न किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें ज्ञान का वरदान प्रदान किया।

द्वापर युग में यह धाम एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक कथा से जुड़ जाता है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों के प्रायश्चित के लिए भगवान शिव की शरण में आए। लेकिन शिव उनसे प्रसन्न नहीं थे और उनसे बचने के लिए उन्होंने महिष अर्थात भैंसे का रूप धारण कर लिया। पांडवों ने इस रहस्य को समझ लिया और उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। जब शिव भूमिगत होने लगे, तब भीम ने उनके पृष्ठ भाग को पकड़ लिया। वही भाग केदारनाथ में शिला रूप में प्रकट हुआ, जबकि शिव के अन्य अंग Madhyamaheshwar Temple, Tungnath Temple, Rudranath Temple और Kalpeshwar Temple में स्थापित हुए। ये सभी मिलकर पंच केदार कहलाते हैं, जो शिव के विभिन्न स्वरूपों की उपासना का केंद्र हैं।

केदारनाथ मंदिर की सबसे अनूठी विशेषता यह है कि यहां भगवान शिव की पूजा त्रिकोणीय शिला के रूप में की जाती है। यह अन्य ज्योतिर्लिंगों से इसे अलग बनाता है, क्योंकि अधिकांश ज्योतिर्लिंग गोलाकार होते हैं, जबकि यहां का लिंग त्रिकोणीय है। इसकी परिधि लगभग ढाई मीटर और ऊंचाई लगभग डेढ़ फीट है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस शिला में मानव सिर की आकृति झलकती है, जो शिव के जीवंत स्वरूप का प्रतीक है। जब भक्त इस शिला के समक्ष खड़ा होता है, तो वह केवल एक पत्थर नहीं देखता, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा का अनुभव करता है, जो उसकी चेतना को स्पर्श करती है।

मंदिर की संरचना भी अपने आप में अद्भुत है। यह मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित है—सभा मंडप और गर्भगृह। सभा मंडप में माता पार्वती, पांचों पांडव, भगवान कृष्ण, नंदी और वीरभद्र की मूर्तियां स्थापित हैं। ये मूर्तियां इस स्थान की पौराणिक और सांस्कृतिक गहराई को दर्शाती हैं। मंदिर के बाहर स्थित नंदी की विशाल प्रतिमा श्रद्धालुओं को शिव भक्ति की ओर प्रेरित करती है और उन्हें यह स्मरण कराती है कि भक्ति का मार्ग समर्पण और विश्वास से होकर गुजरता है। इतिहास के पन्नों में भी केदारनाथ का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था, जिसे बाद में उनके वंशज राजा जनमेजय ने संरक्षित किया। कालांतर में आदि गुरु Adi Shankaracharya ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और इसे पुनः एक प्रमुख धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने यहीं पर समाधि ली थी, जिससे इस स्थान का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। भूगर्भीय दृष्टि से भी केदारनाथ अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मंदिर लघु हिमयुग के दौरान, जो लगभग 1300 से 1900 ईस्वी के बीच का समय था, बर्फ के नीचे दबा रहा होगा। इसके बावजूद इसकी संरचना सुरक्षित रही, जो इसकी अद्भुत निर्माण शैली और मजबूती को दर्शाती है। हिमालय की कठोर जलवायु और प्राकृतिक चुनौतियों के बीच भी यह मंदिर आज अडिग खड़ा है, मानो स्वयं भगवान शिव इसकी रक्षा कर रहे हों।

केदारनाथ मंदिर की पूजा व्यवस्था भी विशेष महत्व रखती है। यहां के मुख्य पुजारी, जिन्हें रावल कहा जाता है, दक्षिण भारत के वीरशैव लिंगायत संप्रदाय से होते हैं। यह परंपरा भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, जहां उत्तर और दक्षिण की परंपराएं एक साथ मिलती हैं। विशेष बात यह है कि रावल स्वयं पूजा नहीं करते, बल्कि पंच पुजारियों में से किसी एक को नियुक्त करते हैं, जो नियमित रूप से पूजा-अर्चना करता है। मंदिर का संचालन Shri Badrinath Kedarnath Temple Committee द्वारा किया जाता है, जो 1948 में स्थापित की गई थी। यह समिति केदारनाथ के साथ-साथ बद्रीनाथ और अन्य संबंधित मंदिरों का प्रबंधन करती है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद यह सुनिश्चित किया जाता है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और उन्हें सहज रूप से दर्शन प्राप्त हो सकें।

केदारनाथ की यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि एक आत्मिक साधना है। यह यात्रा शरीर को थकाती है, लेकिन आत्मा को ऊर्जा से भर देती है। ऊंचे पर्वत, ठंडी हवाएं, संकरे रास्ते और अनिश्चित मौसम—यह सब मिलकर इस यात्रा को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। लेकिन जब भक्त इन सभी बाधाओं को पार करके मंदिर के सामने पहुंचता है, तो उसे जो शांति और संतोष मिलता है, वह शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता।

यह धाम हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करना चाहिए। केदारनाथ की निस्तब्धता में एक ऐसी गूंज है, जो हमें भीतर से जागृत करती है और यह एहसास कराती है कि हम केवल शरीर नहीं, बल्कि एक दिव्य चेतना का हिस्सा हैं। यहां का हर क्षण, हर दृश्य और हर अनुभूति हमें उस परम सत्य के करीब ले जाती है, जो सदा से हमारे भीतर विद्यमान है।

अंततः, केदारनाथ केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक अनुभूति है—एक ऐसी अनुभूति जो मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है। हिमालय की गोद में स्थित यह पवित्र धाम आज भी उसी दिव्यता और ऊर्जा के साथ विद्यमान है, जो हजारों वर्षों पहले थी। यहां की शांति, यहां की भक्ति और यहां की ऊर्जा हमें यह सिखाती है कि सच्चा सुख और शांति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही निहित है, और उसे पाने के लिए हमें केवल अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सामाजिक समरसता महोत्सव : लोकभवन-गांधीनगर

समाज के सुदूरवर्ती व्यक्ति को मुख्यधारा में लाना ही सच्ची राष्ट्रसेवा है : राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू

▸▸ गुजरात की पुण्य भूमि हमेशा सामाजिक न्याय और समरसता की साक्षी रही है : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

▸▸ सामाजिक समरसता और अंत्योदय के संकल्प के साथ लोकभवन में सामाजिक समरसता महोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ

गांधीनगर : बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती के पावन अवसर पर भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में मंगलवार को गांधीनगर स्थित लोकभवन में 'सामाजिक समरसता महोत्सव' आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल आचार्य देवव्रतजी, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी तथा उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी उपस्थित रहे।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने बाबासाहेब आंबेडकर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि बाबासाहेब ने केवल संविधान का निर्माण ही नहीं किया, बल्कि देश की आधुनिक प्रगति और सामाजिक न्याय की मजबूत नींव रखी है। बाबासाहेब ने भगवान बुद्ध के 'भवतु सब्ब मंगलम्' सिद्धांत का अनुसरण करते हुए समतावादी समाज रचने के लिए 'समता' समाचार पत्र द्वारा जनजागृति फैलाई थी।

राष्ट्रपति ने सामाजिक समरसता, शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि समाज के सुदूरवर्ती व्यक्ति को मुख्यधारा में लाना ही सच्ची राष्ट्रसेवा है। बाबासाहेब ने भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित 'प्रतिष्ठा और अवसर की समानता' शब्द ही हमारा अंतिम लक्ष्य है।

बाबासाहेब के 'शिक्षित बनो' संदेश पर बल देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा ही विकास की सच्ची कुंजी है। संविधान में शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। विशेषकर वंचित और पिछड़े वर्गों के लोग अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए प्रेरित हों, यह सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने नैतिक शिक्षा द्वारा सामाजिक समरसता की भावना को मजबूत करने पर विशेष बल दिया।

राज्यपाल आचार्य देवव्रतजी

▸▸ बाबासाहेब ने शिक्षा के माध्यम से संविधान निर्माण द्वारा शोषितों और वंचितों को नई दिशा दी

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 'अंत्योदय' के विचार के साथ सुदूरवर्ती व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए सरकार कटिबद्ध

राष्ट्रपति ने गांवों को भारतीय संस्कृति का वाहक बताते हुए कहा कि देश की आत्मा गांवों में बसती है। समरस भारतीय समाज का निर्माण समरस गांवों के बिना संभव नहीं है। गांवों में आज भी जाति-भेद से ऊपर उठकर जो परस्पर प्रेम और सौहार्द दिखाई देता है, वही सच्ची भारतीयता है। जब गांव आत्मनिर्भर और सुविधायुक्त बनेंगे, तभी भारत सही अर्थों में विकसित बनेगा।

अपने पिता की सीख को याद करते हुए राष्ट्रपति भावुक हुईं और कहा कि जब मैं पढ़ती थी तब मेरे पिता कहते थे; चाहे जितने बड़े बन जाओ, लेकिन हमेशा मुड़कर यह अवश्य देखो कि कोई जरूरतमंद पीछे न रह जाए। आपकी व्यक्तिगत सफलता तभी सार्थक मानी जाएगी जब वह समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में काम आए।

गुजरात के डेयरी उद्योग और पशुपालकों के परिश्रम की प्रशंसा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत आज विश्व में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, जिसमें गुजरात की सहकारी संस्थाओं और पशुपालकों की भूमिका अग्रणी है। इस अवसर पर उन्होंने ओडिशा में पशुपालन मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 'गौ-मित्र' पद की रचना और गौ-सेवा द्वारा रोजगार बढ़ाने के प्रयोगों का भी स्मरण किया।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू

▸▸ समरस गांवों द्वारा ही 'विकसित भारत' की नींव मजबूत होगी : राष्ट्रपति ने सामाजिक समरसता का मंत्र दिया

▸▸ बाबा साहेब के 'शिक्षित बनो' संदेश को चरितार्थ कर वंचितों को सशक्त बनाने का राष्ट्रपति का आह्वान

▸▸ दूध उत्पादन में भारत की वैश्विक उपलब्धि में गुजरात के पशुपालकों के सहयोग को राष्ट्रपति ने सराहा

राष्ट्रपति ने गुजरात में चल रहे सामाजिक समरसतायुक्त सर्वसमावेशी विकास के प्रयासों के लिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नेतृत्व की प्रशंसा की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि गुजरात के लोग अपनी मेहनत से राज्य को पूर्ण रूप से विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे। सामाजिक लोकतंत्र को जीवन पद्धति के रूप में अपनाकर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को जीवित रखने का सभी से अनुरोध किया।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की जयंती के अवसर पर राज्यपाल आचार्य देवव्रतजी ने देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति को गौरवपूर्ण बताते हुए कहा कि उनका जीवन संघर्ष और तपस्या का प्रतीक है। विशेष रूप से आदिवासी समाज में शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करके उन्होंने बेटियों के लिए पथप्रदर्शक का कार्य किया है।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने शिक्षा का मार्ग अपनाकर तथा विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर भारत के संविधान के निर्माण द्वारा शोषितों और वंचितों को नई दिशा दी थी। बाबासाहेब का स्पष्ट मानना था कि न्याय, भाईचारा और समरसता ही राष्ट्र को मजबूत बनाते हैं।

वेदों और शास्त्रों का संदर्भ देते हुए राज्यपाल ने कहा कि भारतीय संस्कृति में जाति-भेद को कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि समय के साथ समाज में प्रवेश कर चुकी कुरीतियों को दूर करने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी और ज्योतिबा फुले जैसे महापुरुषों ने अनेक कार्य किए थे। आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 'अंत्योदय' के विचार के साथ अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए सरकार कटिबद्ध है, ताकि भारत सही अर्थों में आत्मनिर्भर और विकसित बन सके।

राज्यपाल ने अपने संकल्प के बारे में बात करते हुए कहा कि वे गुजरात के 267 तहसीलों में जाकर गांवों में रात्रि विश्राम कर जनसंवाद करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री के 'एक पेड़ मां के नाम' और स्वच्छता अभियान के माध्यम से गांवों का कायाकल्प करना उनका लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ बाबासाहेब ने सभी को समान अवसर और सामाजिक न्याय से नारी शक्ति सहित सभी के विकास की हिमायत की

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संविधान की वंदना के साथ शासन दायित्व संभालकर दलित, पीड़ित, शोषित, वंचितों के कल्याण को प्राथमिकता दी

आगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी और विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा गांवों में शहर जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। उन्होंने राजकोट जिले के लूणीवाव गांव के गरीब परिवार के साथ भोजन करने के प्रसंग को याद करते हुए जोड़ा कि हृदय से हृदय का जुड़ाव ही सच्ची समरसता है।

अंत में राज्यपाल ने आह्वान किया कि हम सभी एक ही ईश्वर की संतान के रूप में भाईचारा और परस्पर सम्मान विकसित करें। बाबासाहेब आंबेडकर के सपने को पूरा करने के लिए एकजुट और सशक्त भारत बनाने के लिए सामाजिक समरसता अनिवार्य है। जब समाज में ऊंच-नीच के भेद समाप्त होंगे और प्रत्येक नागरिक को समान सम्मान मिलेगा, तभी बाबासाहेब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित मानी जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने डॉ. बाबासाहब आंबेडकर की जयंती पर लोकभवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु की उपस्थिति में आयोजित सामाजिक समरसता महोत्सव को बंधुत्व, भाईचारे और एक भारत, श्रेष्ठ भारत को सुदृढ़ करने वाला बताया। उन्होंने डॉ. आंबेडकर को कृतज्ञतापूर्वक भावांजलि देते हुए कहा कि बाबासाहब ने सभी को समान अवसर और सामाजिक न्याय के जरिए नारी शक्ति सहित सभी के विकास की वकालत की थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी डॉ. आंबेडकर के उसी विचार को साकार करने के लिए नारी शक्ति को शासन भागीदारी में अधिक अवसर प्रदान करने के लिए 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के लिए प्रतिबद्ध हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस संदर्भ में कहा कि 16 अप्रैल को आयोजित होने वाले संसद के विशेष सत्र के सुसंगत हर किसी को को नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन करके विकसित भारत के निर्माण में नारी शक्ति के अधिक से अधिक योगदान को प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने डॉ. बाबासाहब द्वारा समानता और समरसता का दायरा बढ़ाने के लिए दिए गए महत्वपूर्ण योगदान का भी स्मरण किया।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संविधान की वंदना के साथ शासन दायित्व संभालकर दलितों, पीड़ितों, शोषितों और वंचितों के कल्याण को प्राथमिकता दी है।

श्री पटेल ने यह भी कहा कि मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जन धन योजना और पीएम स्वामित्व योजना जैसी अनेक जनहितकारी योजनाओं के सबसे अधिक लाभार्थी वंचित, पीड़ित और शोषित समुदाय के लोग हैं।

मुख्यमंत्री ने सामाजिक समरसता के लिए राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी द्वारा राज्य की 267 तहसीलों के गांवों में जाकर रात्रि ठहराव, जनसंवाद और वंचित परिवारों के यहां भोजन करने की पहल की सराहना की।

इतना ही नहीं, उन्होंने इन गांवों में राज्यपाल द्वारा प्राकृतिक खेती, वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान जैसे जनजागरूकता अभियानों में लोगों को जोड़कर सामाजिक समरसता के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण की भी प्रेरणा देने के लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की।

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा भी वंचितों के विकास और सर्वग्राही कल्याण के लिए लागू की गई योजनाओं की सफलता की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने विश्वास व्यक्त किया कि सामाजिक समरसता को गति देकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने में गुजरात अग्रणी रहेगा।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने उपस्थित महानुभावों का स्वागत करते हुए कहा कि गुजरात की यह पुण्यधरा हमेशा सामाजिक न्याय और समरसता की साक्षी रही है। डॉ. बाबासाहब आंबेडकर की जयंती के पावन अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी की उपस्थिति प्रत्येक नागरिक के लिए आशा की किरण बन गई है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान 'संविधान गौरव यात्रा' और 'कन्या केळवणी' (कन्या शिक्षा) जैसे अभियानों के माध्यम से समरसता को आधुनिक स्वरूप दिया है। इस अवसर पर श्री संघवी ने राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी के दृष्टिकोण की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे स्वयं साधारण नागरिक की तरह सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करके गांवों तक पहुंचते हैं और गरीब परिवारों के साथ समय बिताकर उनकी चिंता करते हैं, जो सामाजिक समरसता का उत्तम दृष्टांत है।

उन्होंने यह विश्वास भी व्यक्त किया कि राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात सरकार समाज के सभी वर्गों के समान और सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध रहेगी।

इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. प्रद्युमन वाजा, राज्य मंत्री डॉ. मनीषाबेन वकील, गुजरात के गांवों से आए नागरिक और उनके परिवारजनों के अलावा कई पदाधिकारी और अधिकारी उपस्थित रहे।

अहमदाबाद मण्डल के 4 कर्मचारी संरक्षा पुरस्कार से सम्मानित

दिनांक 13.04.2026 को अहमदाबाद मंडल में रेल संरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश द्वारा मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इन कर्मचारियों ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उच्च स्तर की सतर्कता, सजगता एवं जिम्मेदारी का परिचय दिया, जिसके परिणामस्वरूप संभावित दुर्घटनाओं को टालते हुए सुरक्षित रेल संचालन सुनिश्चित किया गया।

वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी श्री अरविंद कुमार मीणा ने बताया की, पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य यह दर्शाते हैं कि संरक्षा के प्रति सजगता एवं कर्तव्यनिष्ठा से बड़े से बड़े हादसों को भी रोका जा सकता है।

पुरस्कार प्राप्त कर्मचारियों का विवरण निम्नानुसार है:

1. श्री विपुल कुमार कांटेवाला

पॉइंट्समैन, कटारिया (परिचालन विभाग)

दिनांक 11.11.2025 को ड्यूटी के दौरान इन्होंने असाधारण सतर्कता का परिचय देते हुए चलती ट्रेन के एक वैगन में हैंड ब्रेक की कनेक्टिंग रॉड लटकी हुई देखी। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए इन्होंने तत्काल ट्रेन को सुरक्षित रूप से रुकवाया तथा स्टेशन स्टाफ के सहयोग से त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया। उनकी तत्परता एवं सजगता के कारण एक संभावित गंभीर दुर्घटना को टालना संभव हुआ।

2. श्री आकाश सेटा

JE/C&W, साबरमती (यांत्रिक विभाग)

ROH अनुरक्षण के दौरान इन्होंने BLCS वैगनों के Centre Sill में गंभीर संरचनात्मक दरारों की पहचान की। Dye Penetrant Testing (DPT) के माध्यम से त्वरित निराकरण सुनिश्चित करते हुए इन्होंने RDSO दिशा-निर्देशों के अनुसार 45 वैगनों की संयुक्त जांच का नेतृत्व किया। उनकी तकनीकी दक्षता एवं सतर्कता से संभावित बड़ी दुर्घटना को टालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई।

3. श्री किशन एच. ठाकुर

MCF/C&W, साबरमती (यांत्रिक विभाग)

इन्होंने वैगनों के Centre Sill में क्रैक/हेयरलाइन क्रैक का समय रहते पता लगाकर संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचित किया। जांच एवं संयुक्त निरीक्षण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए इन्होंने दोष की पुष्टि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी सजगता एवं तकनीकी दक्षता से संभावित दुर्घटना को रोका जा सका।

4. श्री प्रीतम शर्मा

Fitter-1/C&W, साबरमती (यांत्रिक विभाग)

ROH अनुरक्षण के दौरान इन्होंने सर्वप्रथम संदिग्ध वैगनों में दरारों का पता लगाकर उच्चाधिकारियों को अवगत कराया। इसके फलस्वरूप विस्तृत परीक्षण एवं निरीक्षण कर दोष की पुष्टि की गई। उनकी प्रारंभिक सतर्कता के कारण गंभीर संरचनात्मक खामियों का समय रहते निराकरण संभव हुआ तथा रेल संरक्षा सुनिश्चित की जा सकी।

अहमदाबाद मंडल द्वारा ऐसे कर्मठ एवं सतर्क कर्मचारियों को सम्मानित करना संगठन में संरक्षा संस्कृति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मंडल भविष्य में भी संरक्षा, दक्षता एवं उत्कृष्ट कार्य संस्कृति को निरंतर बढ़ावा देता रहेगा।

नामांकन वापसी का आखिरी दिनः सूरत नगर निगम चुनाव में आज तय होगी असली जंग की तस्वीर

Surat। सूरत नगर निगम चुनाव के लिए आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख होने के चलते शाम तक चुनावी मुकाबले की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। 30 वार्डों की 120 सीटों पर होने जा रहे इस चुनाव में शुरुआती चरण से ही जबरदस्त राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है, जो अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है।

इस चुनाव में कुल 1059 नामांकन फॉर्म भरे गए थे, जो यह दर्शाता है कि इस बार मुकाबला कितना व्यापक और प्रतिस्पर्धी है। हालांकि, वेरिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान 561 फॉर्म रद्द कर दिए गए, जिसके बाद अब 499 उम्मीदवार ही मैदान में बचे हैं। यह संख्या भी कम नहीं मानी जा रही, क्योंकि इसमें प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ-साथ बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल हैं, जो चुनाव को और अधिक रोचक बना रहे हैं।

राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो Bharatiya Janata Party ने सभी 120 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि Indian National Congress के 119 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं Aam Aadmi Party ने 111 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। इसके अलावा अन्य छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या 148 है, जो कई सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय या बहुकोणीय बना सकते हैं।

वेरिफिकेशन के दौरान कुछ उम्मीदवारों के नामांकन तकनीकी कारणों से रद्द भी हुए हैं। इसमें कांग्रेस का एक और आम आदमी पार्टी के तीन उम्मीदवार शामिल हैं। हालांकि, इन रद्दीकरणों का कुल समीकरण पर बड़ा असर नहीं पड़ा, लेकिन इससे यह जरूर स्पष्ट हुआ कि चुनावी प्रक्रिया में तकनीकी सटीकता कितनी महत्वपूर्ण होती है।

अब सबकी नजरें आज की नाम वापसी प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अंतिम समय में कई उम्मीदवार रणनीतिक रूप से अपना नाम वापस ले सकते हैं, जिससे मुकाबला सीधा और स्पष्ट हो जाएगा। खासतौर पर निर्दलीय उम्मीदवारों को लेकर विभिन्न दलों की सक्रियता बढ़ गई है। सूत्रों के अनुसार, बड़े दल अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए निर्दलीयों को मनाने और उन्हें चुनाव से हटाने के प्रयासों में जुटे हुए हैं।

यह स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि स्थानीय निकाय चुनावों में छोटे अंतर से जीत-हार तय होती है। ऐसे में एक भी अतिरिक्त उम्मीदवार वोटों का बंटवारा कर सकता है और परिणाम को प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि नाम वापसी का यह चरण राजनीतिक रणनीति का सबसे संवेदनशील और निर्णायक हिस्सा माना जाता है।

सूरत नगर निगम चुनाव केवल स्थानीय प्रशासन का चुनाव नहीं है, बल्कि यह राज्य की राजनीति का भी एक अहम संकेतक माना जाता है। यहां के परिणाम यह तय कर सकते हैं कि शहरी मतदाता किस दिशा में सोच रहा है और आने वाले बड़े चुनावों में किस दल को बढ़त मिल सकती है।

शाम तक जैसे ही नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होगी, यह साफ हो जाएगा कि किन वार्डों में सीधा मुकाबला होगा और कहां त्रिकोणीय या बहुकोणीय संघर्ष देखने को मिलेगा। इसके बाद सभी दल पूरी ताकत के साथ प्रचार अभियान में जुट जाएंगे और सूरत की सियासी फिजा और भी गर्म होती नजर आएगी।

कुल मिलाकर, आज का दिन सूरत नगर निगम चुनाव के लिए 'निर्णायक छंटनी' का दिन है, जिसके बाद असली मुकाबले की तस्वीर सामने आएगी और शहर की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश करेगी।

बिहार की राजनीति में बदलाव की दस्तकः सम्राट चौधरी के नेतृत्व को लेकर बढ़ी उम्मीदें, नए दौर की संभावनाएं

Surat। बिहार की राजनीति एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है, जहां नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाओं ने राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता तक नई चर्चा और उम्मीदों को जन्म दे दिया है। हिंदी भाषी महासंघ के महासचिव, भाजपा नेता एवं सिवान कबड्डी संघ के अध्यक्ष Arvind Singh ने इस संभावित बदलाव को ऐतिहासिक बताते हुए Samrat Choudhary के नेतृत्व को बिहार के लिए एक नए युग की शुरुआत करार दिया है। उनका मानना है कि यह केवल एक राजनीतिक नियुक्ति नहीं होगी, बल्कि राज्य की दिशा और दशा बदलने वाली एक निर्णायक पहल साबित हो सकती है।

बिहार लंबे समय से गठबंधन राजनीति का केंद्र रहा है, जहां विभिन्न दलों के बीच सत्ता का संतुलन और समीकरण अक्सर बदलते रहे हैं। ऐसे में यदि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी मिलती है, तो यह भाजपा के लिए भी एक ऐतिहासिक क्षण होगा। यह पहली बार होगा जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बनने की स्थिति स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आएगी। अरविंद सिंह ने इसे केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि राजनीतिक संस्कृति में बदलाव की शुरुआत बताया है।

उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब केवल वादों से संतुष्ट नहीं है, बल्कि वह ठोस परिणाम चाहती है। विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे अब प्राथमिकता के केंद्र में हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन अपेक्षाओं को पूरा करने की होगी। हालांकि, उनके संगठनात्मक अनुभव और जमीनी पकड़ को देखते हुए यह उम्मीद की जा रही है कि वे इस चुनौती का सामना प्रभावी तरीके से कर सकेंगे।

अरविंद सिंह ने अपने बयान में यह भी स्पष्ट किया कि बिहार की राजनीति में यह बदलाव अचानक नहीं आया है, बल्कि यह वर्षों के अनुभव, जनमत और राजनीतिक परिस्थितियों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के शीर्ष नेतृत्व द्वारा लिया गया यह निर्णय राज्य के दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखकर किया गया है। यह संकेत देता है कि अब बिहार में एक स्थिर और स्पष्ट नेतृत्व की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

इस पूरे परिदृश्य में Nitish Kumar का नाम भी प्रमुखता से सामने आता है। अरविंद सिंह ने नीतीश कुमार के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में बिहार ने एक लंबा सफर तय किया है। कभी पिछड़ेपन और अव्यवस्था के लिए पहचाना जाने वाला यह राज्य अब विकास और सुशासन के उदाहरण के रूप में देखा जाने लगा है। सड़कों का जाल, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, महिलाओं के सशक्तिकरण की पहल और कानून व्यवस्था में सुधार जैसे कई कदमों ने बिहार की छवि को बदला है।

उन्होंने यह भी कहा कि सम्राट चौधरी के लिए यह एक मजबूत आधार है, जिस पर वे आगे की इमारत खड़ी कर सकते हैं। नीतीश कुमार द्वारा स्थापित सुशासन की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यदि उसमें नई ऊर्जा और नवाचार जोड़े जाएं, तो बिहार विकास के नए आयाम छू सकता है। यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं होगी, बल्कि समाज के हर वर्ग को इसमें भागीदारी निभानी होगी।

अरविंद सिंह ने Narendra Modi के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र सरकार का सहयोग बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देशभर में जो बुनियादी ढांचा विकास, डिजिटल क्रांति और आर्थिक सुधार हुए हैं, उनका लाभ बिहार को भी मिल सकता है। यदि राज्य और केंद्र के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होता है, तो विकास की गति और तेज हो सकती है।

बिहार के संदर्भ में सबसे बड़ी चुनौती हमेशा से रोजगार और पलायन की रही है। लाखों युवाओं को रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। यदि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार बनती है, तो यह अपेक्षा की जाएगी कि वे राज्य में उद्योग, निवेश और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाएं। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।

शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सुधार की अपार संभावनाएं हैं। पिछले वर्षों में इन क्षेत्रों में कुछ प्रगति जरूर हुई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। बेहतर स्कूल, उच्च शिक्षा संस्थान, अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं बिहार को एक मजबूत सामाजिक ढांचा प्रदान कर सकते हैं। यह विकास केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका असर आम नागरिक के जीवन पर दिखाई देना चाहिए।

राजनीतिक दृष्टि से भी यह बदलाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनती है, तो यह आने वाले चुनावों के लिए एक संकेत होगा कि पार्टी अब पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकलकर नए क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। इससे राष्ट्रीय राजनीति पर भी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि बिहार एक बड़ा और महत्वपूर्ण राज्य है।

हालांकि, हर बदलाव के साथ चुनौतियां भी आती हैं। विपक्ष की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि एक मजबूत लोकतंत्र में संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है। सरकार के निर्णयों पर सवाल उठाना, सुझाव देना और जनहित के मुद्दों को सामने लाना विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। इससे शासन प्रणाली अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनती है।

अरविंद सिंह ने अंत में कहा कि बिहार की जनता अब एक नए अध्याय की प्रतीक्षा कर रही है। यह केवल राजनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का अवसर भी है। यदि सम्राट चौधरी इस जिम्मेदारी को संभालते हैं, तो उनके सामने एक सुनहरा मौका होगा कि वे राज्य को नई दिशा दें और उसे विकास, समृद्धि और सम्मान की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं।

कुल मिलाकर, बिहार इस समय एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। यहां से आगे का रास्ता केवल राजनीतिक फैसलों से तय नहीं होगा, बल्कि उन फैसलों के प्रभावी क्रियान्वयन और जनता के विश्वास पर निर्भर करेगा। आने वाला समय यह तय करेगा कि यह बदलाव केवल एक चर्चा बनकर रह जाता है या वास्तव में एक नए युग की शुरुआत का आधार बनता है।

राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का पांचवां दीक्षांत समारोह

सुरक्षा के लिए आवश्यक शस्त्रों तथा साधनों के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बने; इस दिशा में सरकार के ठोस प्रयास : राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी शिक्षा को व्यक्तिगत उन्नति या विकास का नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण का प्रभावी आधार मानते हैं : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल
- राष्ट्र की सुरक्षा केवल सैन्य शक्ति या टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें राष्ट्र का मनोबल और जनमानस की जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण है : राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल
- राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के पांचवें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल सहित विभिन्न संकायों के स्नातक, परास्नातक और पीएचडी के कुल 562 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु

- युवा शक्ति ही देश के सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य का आधार है
- डिजिटल युग में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाओं का महत्व और उनकी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ गई है
- सुरक्षा केवल भौगोलिक सीमाओं या पारंपरिक हथियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि साइबर सुरक्षा, डेटा सुरक्षा और कूटनीति भी पारंपरिक शक्ति जितनी ही महत्वपूर्ण हैं
- साइबर सुरक्षा अब केवल सुरक्षा का विषय नहीं है, बल्कि यह डिजिटल विश्वास का भी अभिन्न अंग है

राज्यपाल आचार्य देवव्रत

- युवा शक्ति देश भक्ति के संकल्प के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के मिशन से जुड़े
- समर्पण, तपस्या और बलिदान की भावना के साथ राष्ट्र के विकास में सहभागी बनकर अपना कर्तव्य पूरा करें

गांधीनगर : राष्ट्रीय सुरक्षा एवं पुलिस प्रशिक्षण क्षेत्र की देश की अग्रणी संस्था, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी (आरआरयू) में मंगलवार को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु की गरिमामय अध्यक्षता में पांचवां दीक्षांत समारोह सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल विशेष रूप से उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के पांचवें दीक्षांत समारोह में दीक्षांत भाषण देते हुए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि दीक्षांत समारोह किसी भी शैक्षणिक संस्था के लिए गौरव का क्षण होता है, क्योंकि वह राष्ट्रहित के लिए शिक्षित, प्रशिक्षित और समर्पित युवा पीढ़ी समाज को समर्पित करती है। उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि यही युवा शक्ति देश के सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इस अवसर पर उन्होंने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान कर विशेष गौरव की भावना व्यक्त की।

राष्ट्रपति ने बदलते समय की सुरक्षा चुनौतियों के बारे में बात करते हुए जोर देकर कहा कि वर्तमान समय में डिजिटल युग के आगमन के साथ साइबर क्राइम, फिशिंग अटैक और डेटा सुरक्षा जैसे नए खतरे देश के सामने बड़े संकट के रूप में उभरे हैं। पहले ये शब्द केवल परिचय तक सीमित थे, लेकिन आज ये वास्तविक चुनौती हैं। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाओं का महत्व तथा जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि देश की सुरक्षा का सुचारु संचालन अब आधुनिक तकनीकी कौशल पर निर्भर है।

राष्ट्रपति ने कहा कि देश को आज ऐसे कुशल पुलिस अधिकारियों की आवश्यकता है जो साइबर अपराधियों को पकड़ने और उन्हें सजा दिलाने के लिए तकनीकी रूप से सक्षम और सशक्त हों। इसके साथ ही न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए ऐसे फॉरेंसिक विशेषज्ञों की भी आवश्यकता है जो न्यायालय की कसौटी पर खरे उतरने वाले प्रमाण प्रस्तुत कर सकें। उन्होंने जोड़ा कि अब सुरक्षा केवल भौगोलिक सीमाओं या पारंपरिक हथियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि साइबर सुरक्षा, डेटा सुरक्षा और कूटनीति पारंपरिक शक्ति जितनी ही महत्वपूर्ण बन गई हैं।

राष्ट्र की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के बारे में बात करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सुरक्षा के लिए आवश्यक शस्त्रों और साधनों के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बने, इस दिशा में सरकार ठोस प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी द्वारा 'डीप टेक' संबंधित नीतियों में उद्योगों के साथ किया गया जुड़ाव प्रशंसनीय है। उन्होंने सुझाव दिया कि रक्षा क्षेत्र में बदलते रुझानों को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी को अपनी रणनीति लगातार अपडेट करनी चाहिए, ताकि देश के आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए सुरक्षित परिवेश मिल सके।

सूचना प्रौद्योगिकी तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि 'इंडिया एआई मिशन' और एआई गवर्नेंस के माध्यम से भारत विश्व पटल पर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर रहा है। 2026 तक भारत इस क्षेत्र में और अधिक सशक्त बनकर उभरेगा, जो देश की सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए गेम-चेंजर सिद्ध होगा। साइबर सुरक्षा अब केवल सुरक्षा का विषय नहीं है, बल्कि यह डिजिटल विश्वास का भी अभिन्न अंग है।

इस अवसर पर राष्ट्रपति ने सुरक्षा बलों के कामकाज की सराहना करते हुए कहा कि हाल ही में नक्सलवाद के विरुद्ध सुरक्षा बलों ने निर्णायक विजय प्राप्त किया है। देश के जिन क्षेत्रों में पहले भय का वातावरण था, वहां आज शांति और सुरक्षा स्थापित हुई है। पहले जहां नक्सलवाद का लाल झंडा लहराता था, वहां आज देश का राष्ट्रध्वज लहरा रहा है। इस सफलता के लिए उन्होंने सभी राज्य पुलिस बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की विशेष प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने जोड़ा कि सुरक्षित वातावरण में ही व्यापार और आर्थिक समृद्धि फलती-फूलती है, इसलिए सुरक्षा कर्मियों का योगदान देश के विकास से सीधे जुड़ा है।

शैक्षणिक और खेल क्षेत्र में यूनिवर्सिटी की उपलब्धियों की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि यह यूनिवर्सिटी खेलकूद और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट कार्य कर रही है। यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और कुश्ती जैसे खेलों में पदक जीतकर संस्था का नाम रोशन किया है। उन्होंने सभी विजेताओं को बधाई देते हुए खेल क्षेत्र में और प्रगति करने के लिए प्रोत्साहित किया।

विशेष रूप से दीक्षांत समारोह में छात्राओं के प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इंजीनियरिंग और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में पदक प्राप्त करने में छात्राएं अग्रणी हैं, यह देखकर अत्यंत खुशी होती है। बेटियों की यह प्रगति दर्शाती है कि वे आने वाले समय में रक्षा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। रक्षा और इंजीनियरिंग में बेटियों की यह प्रगति विकसित भारत का सशक्त चित्र प्रस्तुत करती है।

राष्ट्रपति ने दीक्षित विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे सुरक्षित, न्यायपूर्ण और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें। उन्होंने कहा कि आपके जैसे सक्षम और कुशल पेशेवरों के कारण ही भारत आने वाले समय में विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व के सामने उभरेगा। देश के विकास के मार्ग पर आपकी सुरक्षा और सेवा अनिवार्य है।

राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के पांचवें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रतजी ने युवा शक्ति से देशभक्ति के संकल्प के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के मिशन में जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जिस रक्षा यूनिवर्सिटी का सपना देखा था, वह आज साकार होकर राष्ट्र निर्माण में आधारभूत योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री के मजबूत नेतृत्व और विजन के कारण ही देश में नक्सलवाद जैसी समस्याएं समाप्त हो रही हैं और सुरक्षा व्यवस्था अधिक सुदृढ़ बनी है।

राज्यपाल ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के ऐतिहासिक निर्णय का उल्लेख करते हुए सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति की प्रशंसा की। उन्होंने पौराणिक उदाहरणों के माध्यम से विद्यार्थियों को सत्य के मार्ग पर चलकर विध्वंसक शक्तियों का सामना करने के लिए प्रेरित किया। श्री अजीत डोभाल की उपस्थिति में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश का युवाधन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और आंतरिक तथा बाह्य सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए सज्ज है। अंत में उन्होंने उपाधि धारकों को बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्र के विकास के लिए समर्पण और तपस्या अनिवार्य है। प्रधानमंत्री जिस प्रकार अविरत कार्य कर रहे हैं, उसका अनुसरण करते हुए यदि युवा सुरक्षा मिशन में सहभागी बनेंगे तो भारत की सुरक्षा और अधिक मजबूत होगी। उन्होंने विद्यार्थियों को सीख दी कि युवा अपनी कर्तव्यनिष्ठा द्वारा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दें।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के पांचवें दीक्षांत समारोह में डिग्री हासिल करने वाले विद्यार्थियों-अधिकारियों को राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ देश के लिए समर्पित रहने की प्रेरणा दी। उन्होंने डॉ. बाबासाहब आंबेडकर की जयंती पर उन्हें वंदन करते हुए कहा कि डॉ. आंबेडकर द्वारा दिया गया संविधान समानता, न्याय और स्वतंत्रता के मूल्यों पर आधारित है। मुख्यमंत्री ने संविधान के इस मूल भाव को राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त करने वाले सभी के लिए अत्यंत प्रासंगिक करार दिया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी शिक्षा को व्यक्तिगत उन्नति या विकास का नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण का प्रभावी आधार मानते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि 2010 में श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में स्थापित रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी उनकी ही विजनरी लीडरशिप में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के रूप में राष्ट्रीय फलक पर कार्यरत हुई है।

मुख्यमंत्री ने इस दीक्षांत समारोह में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल को राष्ट्रपति द्वारा दी गई डॉक्टरेट की मानद उपाधि को समग्र सुरक्षा तंत्र के लिए गौरव के समान बताया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रक्षा क्षेत्र में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और टेक्नोसेवी वर्कफोर्स की जो आवश्यकता बताई है, उसे इस यूनिवर्सिटी ने धरातल पर उतारा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले बेटियों की संख्या का स्वागत करते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण में रक्षा क्षेत्र में नारी शक्ति के बढ़ते प्रभाव का उत्कृष्ट उदाहरण है।

उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी को नेशनल सिक्योरिटी, स्ट्रैटेजिक अफेयर्स, साइबर रेजिलिएंस, क्रिमिनल जस्टिस और कोस्टल विजिलेंस को सुदृढ़ करने वाले पाठ्यक्रमों के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने डिग्री धारकों का आह्वान किया कि वे देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के क्षेत्रों में अपने योगदान से प्रधानमंत्री के 'विकसित भारत@2047' के संकल्प को करें।

राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के पांचवें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से नवाजा।

डॉक्टरेट की मानद उपाधि को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल ने कहा कि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दीर्घदृष्टि का परिणाम है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में वर्ष 2008 में उन्होंने इस संस्थान की जो परिकल्पना की थी, वह आज वास्तविकता बनकर देश की सुरक्षा में अभूतपूर्व योगदान दे रही है।

राष्ट्रीय सुरक्षा को एक जटिल विषय करार देते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षा केवल सैन्य शक्ति या टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राष्ट्र का मनोबल और जनमानस की जागरूकता और इच्छाशक्ति सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

श्री डोभाल ने विद्यार्थियों को प्रेरणा देते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सेना या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, परन्तु यह पूरे देश का सामूहिक दायित्व है। सुरक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के पास अद्यतन ज्ञान संपदा, मजबूत चरित्र और परिणाम-उन्मुख दृष्टिकोण होना अनिवार्य है।

उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सुरक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहां 'सिल्वर मेडल' जैसा कुछ नहीं होता, यहां या तो विजय मिलती है या पराजय। यदि आप जीतते हैं तो राष्ट्र सुरक्षित रहता है और यदि हारते हैं तो अस्तित्व ही दांव पर लग जाता है। अंत में उन्होंने युवा दीक्षार्थियों को आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए निरंतर तैयार रहने और राष्ट्र सेवा के मिशन में पूरी क्षमता के साथ जुड़ जाने का आह्वान किया।

उल्लेखनीय है कि कीर्ति चक्र और राष्ट्रपति पुलिस मेडल जैसे सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित श्री अजीत डोभाल भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया क्षेत्र में उनका योगदान अमूल्य है। उनके मार्गदर्शन में भारत की सुरक्षा नीतियां अधिक मजबूत बनी हैं।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री बंडी संजय कुमार ने गुजरात की पवित्र धरती को नमन करते हुए कहा कि यह भूमि महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभभाई पटेल और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि है। उन्होंने डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि आज का दिन केवल डिग्री प्राप्त करने का नहीं, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा और न्याय प्रणाली के संरक्षक बनने के संकल्प का दिन है। उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह संस्थान राष्ट्रीय सुरक्षा, पुलिस व्यवस्था और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की दीर्घकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है।

देश की आंतरिक सुरक्षा के संबंध में बात करते हुए गृह राज्य मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में निर्णायक परिवर्तन किए हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी नेटवर्क को नेस्तनाबूद करके प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सुरक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाया गया है।

उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विचार का उल्लेख करते हुए कहा कि आज के समय में केवल शारीरिक क्षमता ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि देश को टेक्नोलॉजी और आधुनिक चुनौतियों को समझ सके, ऐसे 'ट्रेंड मैनपावर' की जरूरत है। अंत में उन्होंने विद्यार्थियों से अनुरोध करते हुए तीन मूल बातों- सुरक्षा और स्वतंत्रता का समन्वय, न्यायिक सेवा के प्रति निष्ठा और राष्ट्र सेवा के लिए साहस, को जीवन में उतारने का आह्वान किया।

राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. बिमल पटेल ने महानुभावों सहित उपस्थित सभी का स्वागत करते हुए यूनिवर्सिटी की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' और आंतरिक सुरक्षा में वैश्विक लीडर बनने के विजन के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने यूनिवर्सिटी की विभिन्न उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि रक्षा क्षेत्र में विभिन्न कंपनियों के साथ शैक्षणिक भागीदारी और स्मार्ट प्रोग्राम जैसे प्रोजेक्ट्स यूनिवर्सिटी की नई पहल हैं। इसके अलावा, यूनिवर्सिटी द्वारा डेटा मैनेजमेंट सिस्टम और साइबर सुरक्षा शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है, जो डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाएगा। उन्होंने आगे कहा कि यूनिवर्सिटी का लक्ष्य केवल शिक्षा देना नहीं है, बल्कि पुलिस बल को अधिक पेशेवर, नागरिक-केंद्रित और भविष्य के लिए तैयार करना है। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश तक शैक्षणिक और सुरक्षा विषयक गतिविधियों का विस्तार करके राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय सुरक्षा के नए मानदंड स्थापित कर रही है। मॉडल रिसर्च सेंटर के तौर पर उभरी यह यूनिवर्सिटी देश के सर्वांगीण विकास और सुरक्षित भविष्य के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

समारोह के दौरान विभिन्न संकायों के स्नातक, परास्नातक और पीएचडी के कुल 562 विद्यार्थियों को उपाधि दी गई।

समारोह के प्रारंभ में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने रुद्राक्ष का पौधा लगाया। इसके बाद राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी और सरदार वल्लभभाई पटेल की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने महानुभावों और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के साथ फोटो खिंचवाई।

सूरत में अंबेडकर जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई, वाल्मीकि समुदाय के अधिकारों और महिला आरक्षण के मुद्दे पर मांगें रखी गईं

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। भारत रत्न, संविधान के निर्माता, प्रथम विधि मंत्री और गरीबों के मसीहा डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर, गुजरात प्रदेश महानगरपालिका कर्मिक कांग्रेस द्वारा रिंग रोड स्थित डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम सुबह 10:00 बजे आयोजित किया गया। इस अवसर पर डॉ. बाबासाहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और उनके कार्यों को याद किया गया। गुजरात प्रदेश महानगरपालिका कर्मिक कांग्रेस के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।

बाबासाहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद सूरत के न्यू ओपेरा हाउस में कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक को संबोधित करते हुए गुजरात प्रदेश नगर निगम कर्मचारी कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सैयदभाई शेख ने कहा कि वाल्मीकि समुदाय अन्य समुदायों की तुलना में बेहद पिछड़ा हुआ है और शिक्षा के मामले में भी पिछड़ा है। इस समुदाय का वास्तव में विकास होना चाहिए। इस समुदाय का आर्थिक शोषण बंद होना चाहिए और उन्हें पर्याप्त रोजगार और न्याय मिलना चाहिए। वाल्मीकि समुदाय को संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए।

गुजरात प्रदेश नगर निगम कर्मचारी कांग्रेस के अध्यक्ष भाई लाल वैष्णव ने मुख्य सीट से कहा कि वाल्मीकि समुदाय को संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के मंत्र "शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो" को व्यवहार में लाना चाहिए। यदि वाल्मीकि समुदाय संगठित होकर संघर्ष नहीं करेगा, तो समाज में शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ेगा। तब तक समाज प्रगति नहीं कर पाएगा, इसलिए समाज के शिक्षित होने, संगठित होने और संघर्ष करने से ही समाज का भला होगा। समाज के उद्धार और विकास के लिए, समाज के कार्यकर्ताओं को अपने आंतरिक मतभेदों और झगड़ों को भुलाकर समाज की प्रगति के लिए एकजुट होना चाहिए। डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ने हमें संविधान दिया और संविधान के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जो अधिकार प्राप्त हुए, हमें पिछली स्थिति पर विचार करना चाहिए। हमारा समाज उस समय कैसा था और हमें यह सोचना चाहिए कि डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के बलिदान के बाद समाज की क्या स्थिति है। इसीलिए समाज को एकजुट होकर समाज के विकास के लिए काम करना चाहिए।

हम देश के प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए लाए जा रहे आरक्षण कानून का स्वागत करते हैं, जिसमें उन्होंने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात कही है। साथ ही, हम यह भी मांग करते हैं कि जिला पंचायत, तालुका पंचायत, नगरपालिका और नगर निगम में, जहां महिलाओं को 30% आरक्षण का लाभ दिया गया है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को इससे वंचित रखा गया है, जिसके कारण इस समुदाय की महिलाओं को चुनाव लड़ने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। यदि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लाना है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। जब तक कानून में यह प्रावधान नहीं किया जाता, इस समुदाय की महिलाओं का उद्धार संभव नहीं है। यदि यह कानून वास्तव में महिलाओं के विकास के लिए पारित किया जा रहा है, तो महिलाओं के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। कानून में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी प्रावधान किए जाने चाहिए। और कानून में ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि इन महिलाओं को 7% और 14% का लाभ मिल सके।

इस संगठन ने प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों और महामहिम राष्ट्रपति से समाज की महिलाओं के विकास के लिए कानून में प्रावधान करने की मांग की है। इस बैठक में शशिकांत सोलंकी, कांतिभाई सोलंकी, प्रवीणभाई सोलंकी, अशोकभाई कंथरिया, सुभाषभाई जादे, मेडिकल कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रोफेसर एस.एल. कंथरिया, महासचिव विशालभाई मुंशी और अन्य सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।

सुप्रीम कोर्ट में सवाल : क्या घायल कैडेटों को पूर्व सैनिक का दर्जा और नौकरियों में आरक्षण मिलेगा?

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या सेना में चयनित होने के बाद प्रशिक्षण के दौरान घायल या विकलांग हो जाने वाले सैन्य कैडेटों को पूर्व सैनिक का दर्जा दिया जा सकता है और क्या उन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इन युवा कैडेटों की रोजगार संबंधी जरूरतों और चुनौतियों पर चिंता व्यक्त की है।

सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को इन मुद्दों पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रशिक्षण के दौरान चोट या विकलांगता के कारण कैडेटों को होने वाली कठिनाइयों से संबंधित मामले की सर्वोच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई कर रहा है। सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और उज्ज्वल भुयान की पीठ ने गौर किया कि अधिकांश सैन्य कैडेट 30 वर्ष से कम आयु के हैं और उन्हें रोजगार की सख्त जरूरत है। क्या चिकित्सा कारणों से बाहर किए गए कैडेट सरकारी और अर्ध-प्रतिष्ठित पदों में आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं? इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरामन ने आश्वासन दिया कि इस मामले पर विस्तृत जवाब दिया जाएगा।

500 कैडेटों की समस्या

1985 से अब तक, विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं के कारण लगभग 500 कैडेटों को प्रशिक्षण से मुक्त कर दिया गया है। इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता ने इन कैडेटों की समस्याओं को एक नए स्तर पर पहुँचाया है, जिससे उनके अधिकारों और अवसरों की रक्षा हुई है।

भीषण गर्मी में सूरत का बड़ा फैसला: दोपहर में बंद रहेंगे ट्रैफिक सिग्नल, सड़कों पर मिलेगी राहत

Surat। भीषण गर्मी से जूझ रहे सूरत शहर में नागरिकों को राहत देने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एक अनोखा और व्यावहारिक कदम उठाया है। लगातार बढ़ते तापमान और दोपहर के समय सड़कों पर महसूस हो रही तेज लू को देखते हुए प्रशासन ने 15 अप्रैल से शहर के प्रमुख चौराहों पर दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल बंद रखने का निर्णय लिया है।

पिछले कुछ दिनों से शहर में तापमान तेजी से बढ़ रहा है और 14 अप्रैल को अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में यह आंकड़ा 40 डिग्री के पार भी जा सकता है। ऐसे में दोपहर के समय सड़क पर खड़े रहना खासकर दोपहिया चालकों के लिए बेहद जोखिम भरा साबित हो रहा है, जिससे हीटस्ट्रोक जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ गया है।

इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने यह व्यवस्था लागू की है कि जहां ट्रैफिक कम होगा, वहां सिग्नल पूरी तरह बंद रहेंगे या ब्लिंकिंग मोड पर चलाए जाएंगे। हालांकि, पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस दौरान सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। शहर के प्रमुख और संवेदनशील चौराहों पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी और ट्रैफिक ब्रिगेड के सदस्य तैनात रहेंगे, जो वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करेंगे और दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करेंगे।

इस फैसले के साथ ही प्रशासन ने एक और राहत भरा कदम उठाया है। शहर की चार प्रमुख सड़कों पर दोपहिया चालकों के लिए आर्टिफिशियल शेड बनाए गए हैं, ताकि वे तेज धूप से बच सकें। यह पहल खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी, जिन्हें दोपहर के समय भी जरूरी काम के लिए बाहर निकलना पड़ता है। ट्रैफिक पुलिस ने चार पहिया वाहन चालकों से भी सहयोग की अपील की है। उनसे कहा गया है कि वे मानवता दिखाते हुए दोपहिया चालकों को प्राथमिकता दें और उन्हें शेड के नीचे खड़े होने का मौका दें, ताकि वे धूप से बच सकें। यह कदम न केवल सामाजिक संवेदनशीलता को दर्शाता है, बल्कि सड़क पर एक सकारात्मक वातावरण बनाने में भी मदद करेगा।

पुलिस ने नागरिकों से यह भी आग्रह किया है कि सिग्नल बंद रहने के दौरान वे और अधिक सतर्कता बरतें। चौराहों पर वाहन चलाते समय गति नियंत्रित रखें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें। यह व्यवस्था तभी सफल होगी जब नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे।

सूरत ट्रैफिक पुलिस का यह निर्णय इस बात का उदाहरण है कि कैसे प्रशासन बदलते मौसम और परिस्थितियों के अनुसार नीतियों में लचीलापन लाकर आम लोगों को राहत दे सकता है। भीषण गर्मी के इस दौर में यह पहल न केवल सुविधाजनक है, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति एक संवेदनशील कदम भी साबित हो रही है।

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल ने वर्ष 2025–26 में राजस्व, ट्रेन संचालन एवं सुरक्षा के क्षेत्र में रचा नया इतिहास

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल ने मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन एवं प्रयासों से वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राजस्व अर्जन, परिचालन दक्षता, यात्री सुविधाओं तथा सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। मंडल ने इस वर्ष कई मानकों पर "अब तक का सर्वश्रेष्ठ" प्रदर्शन दर्ज किया है, जो रेलवे के समग्र विकास और यात्री हितों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह उपलब्धियाँ भविष्य में और बेहतर सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रेरणादायक सिद्ध होंगी।

राजस्व क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ

मंडल द्वारा वर्ष 2025–26 में कुल उत्पन्न राजस्व 1345.63 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.7% अधिक है।

- यात्री राजस्व 313.39 करोड़ (17.9% वृद्धि) – अब तक का सर्वाधिक
- माल राजस्व 975.88 करोड़
- टिकट जांच राजस्व 7.15 करोड़ (48.8% वृद्धि) – अब तक का सर्वाधिक
- विविध राजस्व 30.13 करोड़ (13.9% वृद्धि)

- गैर-किराया राजस्व 4.24 करोड़ (रिकॉर्ड 9% वृद्धि)
- खानपान एवं पार्किंग राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई

मंडल ने एक ही दिन में (04.11.2025 को) 1.34 करोड़ का यात्री राजस्व तथा एक माह में (नवम्बर-2025 में) 29.50 करोड़ का रिकॉर्ड यात्री राजस्व अर्जित किया।

परिचालन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन

मंडल ने माल ढुलाई एवं परिचालन में कई नए कीर्तिमान स्थापित किए—

- उर्वरक की सर्वाधिक मासिक लोडिंग: 94 रेक (दिसम्बर-2025)
- LPG लोडिंग: 77 रेक (अप्रैल 2025)
- एक दिन में 630 वैगनों की लोडिंग
- वर्ष के दौरान 5703 क्रैक ट्रेनों का संचालन
- औसत गति एवं वैगन टर्नअराउंड में सुधार

समयपालन के क्षेत्र में 96.48% की उपलब्धि के साथ मंडल ने पश्चिम रेलवे में प्रथम तथा भारतीय रेलवे में तृतीय स्थान प्राप्त किया।

सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

मंडल ने सुरक्षा के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट कार्य करते हुए—

- 22 लेवल क्रॉसिंग समाप्त कीं
- 05 स्टेशनों पर फायर अलार्म सिस्टम स्थापित
- "जीरो SPAD एवं BOR" उपलब्धि हासिल की
- गिर क्षेत्र में 105 शेरों का सफल संरक्षण सुनिश्चित किया

यात्री सुविधाओं का विस्तार

यात्रियों की सुविधा के लिए—

- 6 स्टेशनों पर FOB निर्माण
- 12 स्टेशनों पर डिजिटल सुविधाएँ
- 14 स्टेशनों का पुनर्विकास
- कवर शेड एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया गया

आधारभूत संरचना एवं तकनीकी विकास

मंडल में ट्रैक, सिग्नल, दूरसंचार एवं विद्युत संरचना में व्यापक सुधार किए गए, जिनमें—

- नए ट्रैक एवं साइडिंग का निर्माण
- 72 किमी OFC बिछाना
- 207 CCTV कैमरों की स्थापना
- 534 KWp सौर ऊर्जा क्षमता का विकास शामिल है

कर्मचारी कल्याण के क्षेत्र में पहल

कर्मचारियों के हित में—

- 96 नए आवास निर्मित
- 1000 से अधिक पदोन्नतियाँ
- स्वास्थ्य सेवाओं का आधुनिकीकरण
- ओपन जिम एवं सामुदायिक सुविधाओं का विकास किया गया
- भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने कहा कि भावनगर मंडल की ये उपलब्धियाँ रेलवे की प्रगतिशील सोच, कुशल प्रबंधन तथा कर्मचारियों के समर्पण का परिणाम हैं। मंडल भविष्य में भी यात्री सुविधाओं के विस्तार, सुरक्षा सुदृढ़ीकरण एवं राजस्व वृद्धि के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा।